(Railways) Bill
The question is:
"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1960-61 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

## The motion was adopted.

Mr. Speaker: I will now put the clauses to the vote of the House.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, how can we have discipline in the House when the hon. Minister of Parliamentary Affairs is moving at the same time when you are on your legs.

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): He should be a model for everyone of us.

The Minister of Finance (Shirl Morarji Desal): The hon. Member was standing at that time.

Shri Khushwaqt Ral (Kheri): Sir, is discipline meant to be observed only by this side?

Mr. Speaker: Order, order: r will now put the clauses to the vote of the House.
The question is:
'That clauses 1, 2 and 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clauses 1, 2 and 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title, were added to the Bill.

Etar Shaheawas Ehan: Sir, I move:

[^0]MARCH 10, 1001 Demand for Grants
(Railurays)
get up and standing somewhere by itself is not an offence or an act of indecorum. In such cases what is usually done is-I have noticed this even during the previous regime that is, before 1947-that as soon the Chair gets up the hon. Member, wherever he might be, sits down immediately.

Shri Hem Barua (Gauhati): That is what I had done.

Mr. Speaker: I know the hon. Member is very decorous. That is what hon. Members ought to do. I hope and trust that this will be observed strictly. It is a courtesy shown to each one of us and to the House as a whole.

Now, the question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.
$12.27 \frac{1}{2}$ hrs.
DEMANDS FOR GRANTS
(RAILWAYS)-1961-62-contd.
Mr. Speaker: The House will now proceed with further discussion of Demand for Grant No. 1 in respect of the Budget (Railways) for 1961-62.

Shri Abdul Latif will kindly continue his speech.

बी क्रमूल लतोष (fिजनोर) : मृहतरिक स्वीकर माहब, वेछतर इसके कि में भपनी तक्रीर का पागाइ ₹सं, मुमे एक बात बरे पफ़्रसोम के साय कहती पढ़ी ती है। मैं मुसलसल दो माल से द्रस मामसे को के कर वकरीर का रहा हों लेकित मेरे किमी एक मृताल्बे को पस बक्ता तक का तो मंजूर किया गया है पोर न ही मुले कोई इत्रला बी गयी कि उसाका हैय हुणा मने प्रपनी क्षसीरों में कित्टी fिनिस्टर भाइड घोर fिनिस्टर ज्वाइण की तथक्जह कर कीजों की तरक्र fिलाई की करा ग्रफां स्रां किर दुलगा जारता है। पहनी बात हो

[श्री श्रन्बत लतीफ]
के बारे में है। मैने भजं किया था कि इस लाइन पर पहले देहरा एक्सप्रेस चलती थी लेकिन बाद में उसको बन्द कर दिया गया था। हस को फिर बलाया जाए।
12.29 hrs.
[Mr. Deputy-Splaker in the Chait]
उसके बाद मैने प्रोर श्री भक्त दरांन जी ने जाकर डिल्टी मिनिस्टर साहिब से इसके बार में गुफ्तगू की प्रोर किष्टी मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि वहृ उस ट्रेन को जलर चलायेंगे। उसके बाद पोलिटिकल कान्फेंस में यह बात भाई थी म्रोर ढित्टी मिनिस्टर साहब गे जनसे-प्राम में एनान किया था कि यह ट्रेन बह्गेगी। नोकन इग वक्त तक उसकी तनफ़ कोई तनउउत्ध नही दी गहं हैं।

जो ट्रेनें हम नाइन पर चल रही हैं उनकी बराब हालत की तरफ़, प्रोर उनके किब्बों की हालत की तरफ़ तवज्जह दिलाई थी । मैंने प्रज़ं किया था कि बह रेलवे ट्रेन नहीं हे बलिक घकड़े है। । उसके श्रन्दर बेठकर इन्मान घूमना है, उसका सग घृमना है प्रोर हिलता हैं। मैने व्वुमूसन फ़स्टं क्लास के हिब्बों की तरफ़ नखज्जह दिनाई यी, लेकिन भाज तक बह डिब्बे प्रपनी जगह पर मोजूद है, उन में कोई रदोबदल नहीं की गई है।
घर जुघबतन राय (खेरी)
कर गाड़ी कहिये ।
ग्वाप्पक महोष $x$ : एक वक्त में एक ही तकरीर हो सकती है ।

पी पाल़ल सतीक : मेने पह पर्ग किया षा कि स्टेघानों पर जक्विया गोण्त का सन्ताम किया आय, क्योंकि मुससमान मुसाकिरों को बहुत तब्नीक्र होती है, लेकिन धाज र्रक इसका कोई इस्तलाम नहीं किया $\boldsymbol{\omega}^{2}$ मम धजं किया बा कि स्टेसनों पर बाय का

निहायत्त नांकिस इन्तजाम है। वह भी भ्रपनी जगह पर कायम है। भ्रलबत्ता एक काम ज बर हुपा कि उस चाय की कीमत एक भ्राना иोर बढ़ गई । कीमत बढ़ गई, लेकिन चाय प्रपनी जगह पर नाकिस ही हैं में भ्रजं करना चाहता हूं कि जब मुसलसल टो सालों से एक चीज की तरफ़ भ्रापकी तवज्जह दिलाई जा रही है तो क्या हमारी तकरीरें इसी काबिल हं ती हैं कि यहां से जाने के बाद उनको रढ़ी की टोकरी में ब्रोड़ दिया जाये । कम से कम इतना तो होना ही चाहिये कि जब तकरीरें हों तो भ्राप हम को यह हत्तना दें कि फला मनालबा जो हम ने रक्षा वह भ्रापको मंज़र है, प्रोर फला बतालबा इस बुनियाद पर मंजूर नहीं हो सकता है। कई मतंबा खुद डिप्टी मिनिस्टर माहब मे मेगी प्रोर भक्त दगंन माहब की मुलाकात हुई, जलसा भ्राम नजीबाबाद पोलिटिकल काफेंस में गेलान हुम्रा, लेकिन सब कुछ्घ बेकार रहा। इसी लाइन पर जो प्लेरफार्मं हैं उन के मुताल्लिक दर्वारण की थी कि उनको उभारा जाये क्योंकि भोरतों पोर बन्वों को बढ़ने में बेइन्नहा तकनीफ़ होती है । लेकिन इस तरफ़ भी कोई तबज्जह नहीं दी गई । मिने डिप्टी मिनिस्टर माहब से द्रस्वास्त की थी कि वह कम मे कम उस राम्ने शे गुउर तो जायें जिससे कि भ्षापका गलनम हो कि जो कुष में पर्ड कर रहा हां उस में कितनी सबाई है। कि्टी मिनिस्टर साहब नि गुमेसे बायदा मी किया बा कि वा आर्येंगे, लेकिन भाज तक वह बहां तारीक नहीं ले गये। घलकत्ता हमारे श्री प्रकाश बीर जास्ती एम० पी० बहां गये मोर परसों की पपनी तकरीर में उन्होंने हम साइन के मुर्तालिक धापके सामने धर्ं किया बा। में घापसे कर्ष करला चाहता हां कि हम सिश्रोम्ट करतो हैं भपनी कांस्टिटुएन्सी को इसीिए लोण हम से मताताला करते हैं। समी एत लियों का बाकमा है, मनने एक

जगह पर रेलव की तरक्की का तर्जकिरा किया पोर बड़े घस्खे प्रल्फ़ाज में किया, तो एक साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा : जंगल में मोर नाबा, किस ने देखा । मुर्मकिन है हिन्दुस्तान में तरक्की हुई हो, लेकिन जिला बिजनोर की जो हालत है बह तो वैसी ही है ।

एक माननीव सबस्र : बिजनौर के तो एक मिनिस्टर साहब भी हैं।

श्री प्रम्बुल लतीक : मिनिस्टर भी है मोर हमारे डिट्टी निनिम्टर साहब का वास्ता भी उस जिले मे है. वह वहां किकार को वहां जाने हैं। यह दग्म्बाम्न में ने ग्राप के सामने फिर पेण की हैं। मैं यद्रां पर कोई सम्बी चोड़ी नग्वतीर करने के लिये नहीं पाया हूं, मं तो सिफ़ं कुछ्ध शिक₹ गिले करने के लिये श्राया हैं। में कम में कम यह जस्र महमूम कग्ता हृं कि जो कृष्ट में ने यहां पर भाप के मामने क्रजं किखा था,प्राप मे न कह का जनग्ल मिनेजर को कहना तो मुर्मकिन था कि. काम हो जाता ।

एक मा नित्य सबस्प : प्राप ने यही तो गल्नी की ।

घी घ्रमूल लतीक : मे यह प्रजं कर्ना चाहता दूं कि पमेहढ़ा गजरोला लाटन पर एक पुलिम धाना है । यहां पर बृनकर रहते हैं पोरे बे कपह़े ब़नते हैं । हम जगह के घ्यास पास भी बहुत बुनकर रहते हैं आो कि क्यहे बृनते हैं पोर बाहर को ले जाने हैं। डम ग्टेशन पर हमेशा मे गा़ी़ ककती पायी थी, यह मिं ने हिए्टी मिनिम्टर माहब से भर्मं किया था प्रोर उन्होंने हो को नोट मी कर लिया था। लेकिन पाज बह गाही बहां नहीं रकती है पोर मोगों को बहृत तकमीक होती है।

धारित्र में कि मेंरी दर्साम्न : कि घाप एक रा गाडी, जाहे बह पमेन्बग हो

या एक्स्प्रंस, जहर बलायं भौन जो तीन गाड़ियां इस वक्त जलती हैं उन में क्रामद रफ्त बहुत रहती है, इस लिये कम से कम इननी सहुलियत हो जाय कि हग ट्रेन में दो उन्ने थंड बलास के पांर एक डिब्बा फस्टं कलाम का नजोबाबाद मे दिल्ली के लिए भ्रटेच हो जाय तािक गजरोबा पर तब्दील कर्ने में लोगों को जहमत न हो । मुबह की गाड़ी में एँ थडं बलाम का डिक्बा रहता है, बार्की का दो गाड़ियों में नहीं रहने । जब नक प्राप नई गाड़ी नहीं चलाते तब तक इन नीन गाड़ियं। मे दो fिख्बे थहं क्लास के प्रोग एः उद्वा फटंड कराम का भरंख क. ग निया जाय नाक्र बहां के ग्हने वाले प्रामार्नी मे दिल्नी प्रा मके ।

मझ क. इनना ही भ्रजं कग्ना था। भ्राण की गेलरे ने जां नग्बती की है, उन से काई इनकाए नही का मकना । हा, हमारं क्नें тग जला नवजज़ दी जाय. एमान हों कि घम लोग कुष्व घंप के मागने प्रजं करे बह पाप गदी की टाष ती में उान ₹ ।
] مسملرم 1 1

 ساتهه كهلى بغتى


 كا كها دهكثى ك اس الا كها مصر موا - مهى
 ماصب اور مגسع, ماصب كى توبه
 s مهى بر دوهرانا جالمعا هی - عهلى 2134 (Ai) L.S.D-5
[شرى عدل لطهفـ]

 تها كه اس لأُ بر بهلع ديهرا العسهريسر جلّى لهى لهكن بعد مهـ الهك بلد كر ديا كها تها - اس كو بهر جلايا [Mr Deputy-Speaker in the Chair] السكعبعد مهيغارٍ شوى بهكتدنرشن
 بار< مه كشعكو كى اور تبتى ملستى ماد ب غ ع عـار ب ساتهه وعد8 كها تها كه



 هلع كى - لهكن اس وقت زكس اس كى
 أهـ
 كى طرن - اور أن غ دَبون كی حالـ كى طرن تو جه دلانی تهى - مهی



 كلس ى دَّه كى طرف توجه دلنى




":


عرض كيا تها كه استيشنون بر زبهـده كوشَت كا اننظام كها جانُع - ذليونאه بنا اس ع كم تـ كم مسلمان مسافرو كو
 اس ك كونى انتظام نهه كها كها كها - مهـ
 K ;



 عرض كونا جاعها مو كه جب مسلسل
 كى توجه دلانى إجا اهى


 اتثا تو هونا هى جاهيُع كه جب كونى





 مكا هونى - جلسع عام نيهعهـابـاك عولهمهكل كانلرنس مهي املى هوا لهكى



درخواست كى تهى كه ان. ك, اوبهارا



 ل داخواله
 أ أ كو معلوم هو, كه جو كهجه مهي عرط

 بهى كها تها كه وا جائهن \& لهكن أه


 مهي ازهو غ اس لانّ C




 كها اور بی< اجه الهاط مه مه كها - تو الهى مادب ن كا - جلمل مهن مو, ناجا كس ن د ديكها -





شُو قهدال لطهف - ملستر بمى
 بهى واسطء اس ملع ع ع - وا وعاى







 '4 أها كو إریع كرتا تو همكن تها يه سبـ كا, موحانا -
 فمّطى كى -

شرى مبدالطهفغ - مهل به عرض

 ,


 < تبئى ملسعر ه عرور كها نها بار انهو





 تهن كإجال اسولت
[شرى مبدل لطهف]


 إيك دَبه فرست كلاس 6 نههشب آباد












- آه كى اكُوب

 جاني - اهسا نه هو كه هم لوك جو كِجه أه 2 ساملع عرل كريى ورا آه ردى كى توكى مهی د'لديى -]

बी बलराज निंह : (किराजाबाद) : उपाध्यक्न महोदय, कई मालों से सदन में एक मांग की जाती है कि रेलव बोरं का दफ्तर जो लगानए बढ़्ता जा गरा है, उम पर जो खंरं हर माल बढ़ता जा रहा ह, रेलबे मंत्रालय का उषर जाना काहिय । में मानता हू कि शायद रेलब मती यह जबाब वें कि कि काम बहा रहा है इस लिये रेलबे बोर्ड में घोर बहुत से घकसरो का

मुकरंर किया जा रह्हा है। लेकिन में जानना चाहना हूं कि जो काम बढ़ रहा है उस से जितना मोचने का काम है, नीति बनाने का वाम है, उस नीति को सोचने में कौन मा काम बढ़ना है। इस बारे में यदि रेनवे मंश्री कुद गफ ई दे सकें तो ग्रच्छ होगा । मैं टृर में गहीं जाना चाहना कि इस माल रेल्व वे की श्राम न्नी मिछले साल से ज्यादा है, नीयन ₹नना जरूर कहना चाहूंगा fि fिद्वंन चान गांच मालों का बजट ध्रगन देग्वा जाये रेंववे त्रोंड का, तों इम में हु मान बढ़नी fदग्रंई्ट देगी। इन के ब्राबज़ करा जाना है कि: हृम मितण्यग्या बनना चुन्ने है । उस नए्फ रनव मंत्री का जरु जन देना नानिय ।

श्रभी प्रश्नां के घंटे में कहा गया स्राँ fिछंत्र पन्द्रह बंस दिनों में नगाना मत्र में यद्ध चर्चा होटी ग्ही है, मदन मे भी हुई है, fि गेन्नवे इस कतंत्य का पालं कग्ने में श्रनमथं ग्ही है कि जां कोग्यला ग्वानंं पर पडा ठुम्रा है ग्ऱा हुग्रा, उसे इडन्ट्रीज भ्रयान् उव्योगां का दे गंक्रो या घरों में गुचा मकें। बार-बार मदन में यह बात कही जाती है। ग्नवे मत्री करने है कि इत में हमारी कांई जज्मदारी नहैं है, ह्दमका जिनना लक्ष्य बनाया गया था दोनों पचवर्षाय यंजनामों के घ्रन गंन, हैम ने उंम प़र कर दि:ा, घौर इस्पात पौर ईंधन मंशो कटे है कि उनका लक्ष्य जितना या उतना ही उन्होंने पूरा किया है, उस मे ज्यादा नहीं । मेरी समक्न में नहीं घाता कि प्रखिर गलती कहां

। मंं कहना नहीं चाहता, लेकिन यदि प्लं निग कमिशन की गलती रही हो तो उन्होंने मही उंग से योजना निमित नहीं की, घौर घय जो कुष हो रहा है उस से मुलक में उत्पादन में कमी हो ग्ही है, जिस मे कि मुलक के लोगों को परेगानी हो रही है। कोयला की कीमतें जगह अगह बहुत बढ़ी हई हैं, छस को घ्यान में रहते हुए कम से

क.म तृतीय पंच वर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए वंगन्स की जो स्थिति है उस को सही ठंग से ठीक करने की कोंशिश की जाय । यदि भ्राप के श्रायोजक यह भी नहीं देख मकते कि जो योजना बन रही हैंभर मल्य. में जो टक्नालोजी की उन्नति हो रही है, दूसरे क्षे र्ंों में जो उभ्नति हो गही है, उस से कितना उत्पादन बढ़ेगा श्रोण कितना कोगला इस्तेमाल कर्ने की जरूग्त पड़ेगी, तो गह वि.सी तग्र की ल्लेनिग नही है। इस मन्दर्भं में त्तीय पंचवर्षोय गोजना के श्रन्तगंत जो कुछ्ब रेलों के विकाम की ग्यदस्था की गई है, में ममझ्नता हुं कि. बत्र भी श्रागका पूरा मामान म्रोग ग्या प्रियों को ने जाने में म्रममथं होगी। इर्मनिय प्रब ममय है कि इसी वक्त से इम पर विजार कि,या जाय प्रोग देबा जाय कि तृतीय पचवर्षीय योजना के फ्रन्नगंत व भी भी इस नग्र की कोई दिवबन न क्राय जि.ममें मांल एक जगह मे द्रूसरी जगः म जा न्वं।

इस सन्दभं में प्रष्न श्राना है कि. जो भ्रापका रोलिग स्टाक है उसके गम्बःध में सग्कार की पोर रेलवे मन्गालय की क्या नीति है। वेगन्म के बारे में कहां जाता है कि हमारे पास कमी है। प्राज मे ₹ई साल पहलने से बंगन्म बनाय जाने चाहियें थे । वकंहाप में काम लिया जा सक्ता था, नेकेन नही लिया गया। क्यां नही fलया गया, इस पर प्रबास पड़ना वाहिये। भाज मे बर्ड माल पहीले हम मोष मकते षे कि तो लोकोमोटिबक हुम बाहु से मंगाते हैं ठीजल प्रोग एलेष्ट्रिक के उनके बारे में क्या किता जाय। एसे क्ट्रूक के बारे में कहा जा ंकता या कि हम उनको नहीं बना सकते, लेः न हीजल लोकोमांटिट्ज के बारे में हमने पहलं से योजना क्यों नहीं बनाई ताकि उनका उत्पादन मुल्क में हो सके । इस मंबर्म में जब हम देक्षते हैं कि थमरीका से हमं ही० एस० एफ लोन मिलता है रेकों के पुर्ननिर्माज के लिय जोर विभाम के लिय तो हम को सोषना चाईये कि हम बहां से जो लोषो-

मोटिष्ज खरीदते हैं ठीजल के उस में बहु मनकंता बग्ती जा रही है या नहीं जो कि बग्ती जानी चाहिय । पभी पिष्षसे दिनों लोकोमोटिठज लरीदने के सम्बन्ध में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि बेंसे तो लोकोमोटिक्म की बरीद के लिए ग्लोबल टंडंडं मांगे जाते हैं लेकिन डी० एल० एक० लोन की यह चु कि शतं थी कि केवल पमरीका मे ही इय रुण् से लोकोमोटिव खरीदे जायं, इर्नलए भमरीका से ही टेठ मांगे गए । श्रमरीका में तीन फर्म लोकोमोटिव बनाती हैं, लेबिन जो उत्तर दिया गया उपसे पता बरता है कि ज्यादा कीमत बाने टेंड को मंज़ किया गया पोर कम कीमन वाले टेंटर का मंजूर नहीं किया गया। में उमकी विणषनंमों में गहीं जाना चाहता । हो मवता है कि रेलवे मन्र्जलय यह जबाब दे कि क.स कीमत नाले टें $\begin{aligned} & \text { के लोकोमोटिव में कुम्य गरबी }\end{aligned}$ थी जो कि त्रूमे में नहीं थी। में मानता हूं कर: ही० ए़न० एक० लोन की यह धारं है कि. उमसे हम दुनिया के बाजा मे लोकोमांटिव नही खरीद गकते, हमकों पमरीका के बाजाग से ही बररीदने होंग, लेकिन क्रमरीका में भी जिभका टेछ का कीमत का है उसको मंजूर न करना पोर जिसका ज्यासा कीमन का है उमको भंजूर कर्ना मे समसता हुं कि यह उचित नहीं हैं । में जाहगा कि मन्न्जी महोंदय इम घोग ध्यान वे क्यांकि र्भविध्य में हरमें पोग कीज मी खरीदनी होंीी। तर श्राम पर यह कर्षा होती है कि दू जातों में कुष गड़बड़ होती है। में नहीं कह मकता f. इममें कोई भाषार है या नहीं, लेकिन जब बम कीमत का टेंहर मंूूर नही किया आया जरे उ्याजा कीमत जाला मंतूर किया आया है तो इस प्रकाए की णकाएँ गंधा होने की गु जाइए हुंती है। यं बाहुणा कि हल प्रकार की शकाषां को दूर कग्ने की अष्ट कोरिण का जाए।
 क्ष कहा गया है कीर तो कण का किक्र किया

## [ श्री बजराज fिंत ]

गया है। इम सम्बन्ध में रेलवे मन्त्रालय की एक कमेटी बं १ री श्रोग उसने कुछ नीfन निर्षारित की थी उस पर चलने की रेल मन्त्रालय सोचता था, लेकिन श्रफसोस है कि श्रब उस नीति पर भी नहां चंता जा रह़ा है । जहां तक केटरग्रि का मम्बन्ध है केवल खोने पीने की चीजों का श्राप डिपार्टमेंटनाइजेगन करते है, मिफं बेचने की चीजों का विभागीकरण कग्ने हैं। इमसे लोगों के दिमाग में यद बात पैदा हो ही है कि शायद श्राप कहीं होटल खोलने जा गहे हैं। इन विचारों से उन लोगों की बात को बल मिलता है जो गष्ट्रीयकरण नहीं चाहते । जब मे श्रापने केटरिंग श्रपने हाथ में लिया है तब मे जनना को चीजें ग्वरत्र मिलने लगी है । श्राप देग्रेंगे कि इन बातों से जनता के दिमाग में राष्ट्रीयकग्ण के विरुद्ध भावना पदा होती है । मैं तो चाहता हूं कि मूल्क में जल्दी मे जन्दी ममाजवाद कायम किया जाए । लेकिन भ्रगर समाजवाद के नाम पर एसी बतें होंगी तो लोगों के मन में राप्ट्रीयक र्ण के प्रनि दुर्भावना पंदा होगी जो कि उचित नहीं है। में उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि हमते जो केटगिग स्टेगनों पर भपने हाष में लिया है उससे एक तरफ तो नुकसान हो गहा है श्रोर उसी के माथ साथ हमको ध्रच्छा खाना नहीं मिलता । श्रापकी सर विस घच्ही नही होती। बासी खाना दिया जाता है। यह्ह सारी चीजें हो रही हैं मौर रेलवे मन्त्रालय इस दिशा में कुष्ब नहीं कर रहा है।

Shri Sonavane (Sholapur-ReservedSech. Castes): That is not correct.

Shri M. B. Thakore: (Patan): That is correct.

Mr. Depaty-Speaker: Order, order; the hon. Member may be allowed to go on.

ती च्राराज fिह्: कोई देखना चाहे तो इस कीज को देल सकता है। उस तरक से घान!ज भारी कि ऐसी बता नहीं है । में

चाहुता हूं कि रेलवे मत्त्रालय एक बात के लिए तैयार हो जाए कि इन चीजों को देखने के लिए ग्रोर इनकी जांच पड़ताल करने के लिए एक पालियामेंटरी कमेटी, स्टेंडिंग कमेटी, बनाए जो रेलवे की सब चीजों की जांच पड़ताल करे । लेकिन केटरिंग के बारे में तो मैं चाह्ता हूं कि खास तोर पर जांच पड़नाल की जाए।

में जानता हृं कि कांग्रेस पार्टी की एक कममटी ने यद सिफार्शि की थी कि पबिलक भंडग्रेकिंग की जांच पड़ताल के लिए एक स्टेडिग कमेटी होनी चाहिए । रेलवे विभाग तो एक बहुन त्रड़ा घ्रंडग्टेक्रग है, इसमें हजारों करांड़ों का लेन देन होता है । में चाहूंगा कि रेलवे मन्त्रालय इस बात पर विचार करे कि रेलवे के फाइनेंस, चल स्टाक घ्रादि दुमरी श्रोर चीजों की भी जांच पड़नाल कर्ने के निये एक. म्टेंडिंग कमेटी इम 'ार्नियमेंट के मेम्नरों की वनायी जएए जो f क इन चांजो पर ध्यान दे मके।

तो में कटरिंत के बारे में कह रहा था। मैं चाहता हूं कि यहु दे नेखा जाए कि केटारग में किस प्रनार उम्नति की जा सकत्वी है। यह मिफं श्रपर क्लाम के लोगों की सुविधा के लिए ही नही हांना चाहिए । थडं क्लःस के मुम फिरों की मुविधामों का भी पूरा ध्यान रग्वना चहिए क्योंकि रेलवे की ज्यादातर भाभदनी उनसे ही होती है। इससे केवल भपर क्लास वालो को ही कायदा न हो । इम पर रेलवे मत्त्रालय को पुन: विचार करने की जहारन है।

सरकार की यह नाति रही है कि जो लाइनें लड़ाई के जमाने में उखाढ़ ली गयी थी उनको फिर से लगा दिय जाए घौर देश में ऐसी भषषिकांश लाइनें फिर से लगा दी गयी हैं, लेकिन में जनना चह्ता हं कि भागरा जिला में एक लाइन यी आागरा से बाह तक, ओो कि $\gamma 0-\gamma \times$ मील लम्बी लाइन बी, पौर

जिसको लड़ाई के जमाने में उखाड़ लिया गया था, उसकी घ्रोर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है । प्रापकी यह नीति है कि देग मे जिन लाइनों का लड़ार्ड के जमाने में उखाड़ा गया था उनको किर मे लगा दिया जाए प्रौर प्रापने ऐसी लाइनों को लगाने की कोशिधा भी की है। मिं चाहंगा कि इस लाइन को भी फिर से लगाने पर विचार किया जाए।

दृघंटनाम्रों के बारें मे सदन में चर्चा हृई है। प्रभ्भा हममने गेलने की लापरवाही के कारण देग का एक बहुन बड़ा प्रकार सो दिया। पर्मों तग्मों एव दुघंटना में ??-१४ प्रार्दमयों की जानें गई हैं। विद्धने कुछ दिनों से हम देखते थे बि दुघंटनायें नहीं हो गही थीं लेकिन श्रब किर उनकी लहुर सी प्रा ग्ही है। में चहूंगा वि. रेलबे मन्श्रालय इम तरफ विशेव तोर से ध्यान दे ताकि इम प्रकार की दुघंटनायें भविध्य में नहाने पावे।

मे एक निवेदन कर्ना चाहना है इलेक्ट्रिफिकहन के बाने में । श्रपपने हान में मुगलमगन प्रोर हातबड़ा कर बीच में ठनेक्ट्र्ड फिक्धचन कि,या है जहां पर्तांयंत्र का क्षेत्र भी है । जो लाइनें कोयला क्षेत्र स दूर हैं उनमें कभी कभी एर्मा म्थिति हों जार्ता है किः वे बन्द हों ग्ही हैं । इरनियये भ्रग भ्रापको इनेक्ट्रिफिकरान करना है तो एस म्थानों में कर्ना चाहिये जेंश कि पंजब, महाराप्ट्र पोर गुजगन जा fि: कायला क्षेत्र म यहुंत दूर है।

Shri M. B. Thakore: There are no lines; what to talk of Electrification'.

थी ब्रजराज नित् : मे चाहूंगा कि भविव्य में मह नीनि भ्रपायी जाए कि उन स्व नों में पहने इलेक्द्रिफिकेसान किया जाए जो कि फंक्षा क्षेत्र को दूर है करे कहां कोयला बहुचने में दिककत होती है ताकि बहां के मोबों को कोषले की कमी के काल कहिनाई का सामना न करण। वह़े।

जो वक्सं, मैलीनरी मोर रोलिल क्टाक प्रोशाम हम को दिया गया है उमये चालम

होता है कि घ्बोटी घोटी चीजों के निर्माण के लिए डेढ़ डेग़ीपोर दो दों लाख रुपया रला गया है। में समनता हूं कि यह् देसना चहियें कि इतना रवया किस प्रकार खर्य होता है । उदाहरण के लिए भाप देलें कि टूंजला के स्टेगन पर एक भोबर किज के लिए एक लाख रुपया रखा गया है। इतना रुपया इस पर कैसे बरं हो सकता है यह मेरी समझ्भ में नही पालत। में सभझ्लता हूं कि जितना रुपया हृम लर्य के लिए ग्ब रहे हैं उतना खर्वं नहीं होता । इममें कुछ न कुष्व गड़बड़ो जसूर है। में चाहूंगा कि. रेलवे मन्री इस पर ह्यान वें कि बाजार में चोजों का कीमते देवते हैए ये काम कम रपए में हाॅने चाहियें। प्रापको तो सारा सामान उचित मूल्य कर मिलता है फिर छयों दूसरी जगए गं ज्यादा तेज चंजें बननी चाहियें यह देखा जनाना चैंहिये कि हमारा रुपया ठीक तरह से तो प्वं हो रहा है। बीच में कोई गب़बड़ी तो नहीं है । में जाहांगा कि रेलबे मन्ती जल्र इबर ध्यान दें कि सहीं ऐंमा तो नहीं है कि हमाग पेस। प्रच्छे तरींकें में खवं न हां रहा हां जेंय कि होना चाहिए।

भ्रन्न में में रेलबे के रालिग स्टाक की गनिखिषि प्रोग स्पीड कं, बते में कुस निवेषन कग्ना चाहुता हृं। यह्ह पभी मम्तापजनक नहीं है। यदि हुम घपने क्विगंस ओो कि हुमाे पाम हैं मीर जेनी हमारी पोगीणन है उममें किसी नरीके: मे प्रगर एक्ष घंटे उनले भीर प्रश्रुिक काम के मक लो बह़त्रुर्रति हो मकर्ता है में ममभता क्रें कि सब तरीको स ज्रगर हम इम पर ज्यान वे तो भुदिकान नहीं होगा। यदि हम घवने क्गस स एक बहे प्रािं म मयय काम से मकने में समर्य हो जायें तो पाज हमारे वेका में कोयके जोट धृमरे सामान को ठोने को तो समस्पा है फोर क्षैंम की गो कमी घनुषष की चा दरी है, उस की स्थिति काफी गुष् सकती है। मुमे धफमास है कि वह नहीं हां पावा है। कभी करी कहा ज्ता है कि ऐंसा इमालयं कही हों चा है क्योंति उमागे गाम कानूत कहीं है वाकि

## [:्री क्रजराज सिंह]

लोगो को मजबूर किया जा सके कि वे सामान जल्दी में उठाये।

नई दिल्ली के बाने में कहा गया है । मे भ्रापको विश्वाम दिनाना चाहता हैं कि यदि भ्राप इससे सम्बन्बित कानृन में कोई कड़ापन लाना चाहते हैं नो अ्राप श्रपना प्रवोजल लेकर इम मदन के मामने प्राइये प्रोर उसके लिए मबसे मदसे पहने रजामन्द हो जायगा कि हमारी गेलवेज का चल स्टाक जल्दी जल्दी हिंने जुले। क. नून का बहाना बना कंत मुल्क का मामान पक जगही मे दूपरी द्वसरी जगह न जा मके, तो यहि उचिन वतन न्ही होगी । मै चहूंगा किं हुमाेे रेलवे मन्त्री महोलय इस विषय मे जर। गभ्भीग्ता में जांच पड़न्ताल करायें प्रोर स्वय देखे कि म्राज हम चन स्टाक से जितना मामान निये जा रहे हैं वह क्या सन्तोपप्रद है प्रोर काया श्रपने वैगंम से एक घंटे रोज श्रधिक काम नहीं निया जा सकता है ? कहीं ऐेगा तो नहीं होता है कि वैगंय हमारे कही कहीं एक एक प्रोग दो, दो दिन पड़े रहते हैं ? प्रधिक काम लेने के लिए यदि किसी कानून में परिखर्तन कर्ने की जसरतत हो तो कानून में तबदीली कर लें । भाज मुल्क की श्रावश्यकता इस बात की है $\mathrm{f}_{\mathrm{F}}$ देक्ष मे जो भी उत्पादन हो रहा है, कच्चे माल भोर फिनिश्ड गुड्स का तमाम उत्पादित माल एक जगहु से दूसरी जगह तेजी के साथ पोर समय के भ्रन्दर पहुंचे।

भभी चर्षा हो यही थी कि हम विदेशों को $x, x$ लाल टन तीनी भेजने बाले हैं । $\gamma, x$ लाब टन बीनी को कारलानों मे पोट तक ले जाना है उसके लिए कम से कम ३०००० वेगंम जाहियें । इसी तरह स देश में कोयले का उत्वादन बढ़ रहा है जलरी बा़ है कि जितने हमारे पास वैगंस हैं उनसे हम कम से कम एक बंटे ज्यादा काम से सकें। रसी बरींक से फपनी लाइस को केपेसिटी को

बढ़ाने की कोशिश करें । रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाने की कोशिश करें म्रोर 90, P4 मिनट का फी फर्क श्रगर हम डाल सकते हैं तो डालें । मुझे बतलाया गया है कि जापान में रेलें बहुत तेज दोड़तो हैं। मुझे पता नहीं कि हिन्दुम्तान में इस स्पीड को बढ़ाने की दिशा में कोर्ई एक्सपेरीमेंट कयों नहीं किया जाता । इम बान की जांच होनी चाहिये कि हिन्दुस्तान में हैम श्रयनी गेलगाड़ियों को क्या प्रोर तेज नहीं चला सकते हैं। क्या हम श्रपनी गाड़ियों को फीक्वेंमी नह़ी बढ़ा सकते हैं, दस, दम प्रोर पन्द्रह, पन्द्रह मिनें के बाद क्या हैम श्रपनी पे मेंजर ट्रेंम प्रोर गुड्म ट्रेन नही छोड़ु मकते हैं ? में ममझना हूं कि प्रणर इस विषय में जांच पड़नाल की जाय प्रोर उसके लिए कोगिश की जाय तो यह़ मब हो मकना है ग्रोर जहुन एक ऐमी स्थिति श्रा सकती है जिसमें हम श्रपना माल ज्यादा श्रोर घ्रधिक सीघ्रता म ढां मके श्रोर प्रवन वे मेंजमं का प्रोर श्रधिक तादाद में घ्रोर तेजी के माध एक जगह् मे दूभरी जगह् पचा महूंनें।

मुझे प्रोर विशेष नहीं कहृना है । में मिफं यही कहना चहिंगा कि हमारी रेलत्रेज को कर्मी़यल लाइन्स पर बलने हुए सेवा करनी चाहिए जैंग कि हमारे वित्त मन्री महोदय ने जनता पर करों का भार बढ़ा दिया है हमारी रेलवेज को जनता पर टैक्स लगाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पषितु उसे तो एक कमघिंयल सबिस के तौर पर घ्रपना काम करते रहगा चरिए ।

Shri T. Subramanyam (Bellary): The railways constitute our greatest national undertaking with a capital-at-charge of Rs. 1560 crores, and employing about $11,60,000$ people. It purports to play the dual role of public utility undertaling as well as a commercial enterprise.

We have various modes of transport in our country, the roadways,
the railways, the waterways, and the airways also. We must have a national policy of integrating all these modes of transport, if the needs of the rrowing economy and the development of our country have to be met satisfactorily and adequately. A committee has been appointed, which is known as the Neogy Committee, to recommend what properly should be the long-term transport policy of the country, so that the development of the transport machinery may serve the growing needs with economy and efficiency, avoiding duplication, and also the role of the various modes of transport in the coming five to ten years; also, the mechanisin to regulate and control the various modes of transport and co-ordinate their activities has to be recommended by this committee. An interim report has been received, and I hope that Government will take speedy action with regard to this matter.

We have undertaken to build up the socio-economic welfare of over forty crore; of people, and industrialisation is going on at a very speedy rate, but, unfortunately we find that the modes of transport are not able to cope up with the demands and the requirements. That has been our experience. Almost every day, in the Parliament, the question comes up that wagons are not available to lift up the coal. Even the Food and Agriculture Minister was complaining that adequate number of wagons were not available even to lift foodgrains from one place to another. This question has been coming up frequently before this House in connection with transport of steel, minerals etc. The railways have aleo been set the task of taking up greater and greater responsibilities in the Third Five Year Plan. Therefore, I urge that immediately, a decision should be taken with regard to co-ordinating the various modes of transport. At the same time, there should be a vigorous sort of search or introspection on the part of
the Railway Board to cope up with the needs of the developing economy.

In the Third Five Year Plan, the task has been set for the railways to lift 93,000 million ton-miles, and that will mean an incerase from the Second Plan target of 54,000 million ton-miles. The increase will be of of the order of nearly 39,000 million ton-miles. It is a huge task, almost double the work that was taken up in the Second Plan. I again urge the Railway Board and the Railway Ministry to have a vigorous search with regard to this matter.

In the Second Five Year Plan, for the development of railways, Rs. 1121.5 crores were invested. In the Third Plan, it is proposed tentatively that Rs. 1255 crores should be invested. The Second Plan targets with regard to the receipt of locomotives, coaching-stock and wagons, we are told, will be almost fulfilled. In the Second Plan, about 2100 locomotives, 8500 coachingstock, and about a lakh of wagons will be received by the end of this month. That is a matter for gratifcation. In the Third Plan, we are told that 1700 locomotives, 7800 coaching-stock and 110,000 wagons will be received. We are also told that we shall be attaining selfsufficiency with regard to the equipment of our railways.

In the Second Plan, 800 miles of new railway construction were undertaken. We are told that that also will be practically reached. This represents mainly the requirements of the steel and coal industries, and the operational requirements of the railways themselves. We are told that in the Third Plan also, the same programme will continue, and about 1100 miles of new railway construction will be undertaken.

In this context. I must say that there $i_{s}$ an acute feeling of dissatisfaction in South India. and 1 shall be failing in my duty, if I do not give expression to that cort of feeling. It
[Shri T. Subramanyam]
is a bad thing to allow that sort of feeling to continue. It is also a fact that in the Third Five Year Plan also, according to the proposals made, we do not have any railway constructions in South India.

The hon. Minister has said in his budget speech at page 13 , that
"In the matter of construction of new lines the Planning Commission have so far allotted Rs, 120 crores. This will provide for approximately 1160 miles, representing lines essentially required either in connection with the Railways' operational needs or in connection with the development of industries and $\mathrm{m} . \mathrm{c}^{\prime}$ al resources. The latter include 200 miles for development of new coal fields and about 50 miles for a new line to serve the proposed port at Haldia. The provision for new lines is being reviewed in consultation with the Planning Commission.".
That gives a little margin of hope for us. We are further informed:
"I am hopeful that it will be found possible to make a further allocation of funds, to meet the demands for new lines to be constructed on grounds of political, social and economic development in certain areas more particularly in the South.".

That is a gratifying and heartening thing. The word 'political' also has been advisedly. I presume, because that feeling does exist. Of course, it is based on very justiflable and very solid grounds. No new railway construction has been undertaken; and after the reorganisation of States, since 1956, there has been a very acute need for new lines being constructed. As you know, geographically, as we proceed towards Cape Comorin the land tapers, and the inter-links that have to be added would be very narrow, sometimes 40 miles, sometimes 50 miles and so on, and they will be not more than 100
miles generally. If these links are constructed then the way will be opened for the development of industries, and for enterprise and for trade and commerce.

13 hrs .
I would like to mention the lines that should be taken up immediately in South India. We have been agitating for them since 1956; the demand has been insistent and it has to be satisfied. It is a case of must, I say. The lines are: HasanMangalore, Kottur-Harihar, Rayad-dug-Chitaldrug, Hubli-Karwar and Salem-Bangalore. Priority should be given to these lines. We do recognise that there is very great need to give priority for the defence of our country and for the development of iron and steel industry, as also for the operational requirements of the railways themselves. After satisfying these three requirements. I would urge the Government to take up these railway lines in South India and satiffying the insistent demands there. It has been recognised by the Planning Commission and I hope Government will come to a speedy decision with regard to this matter.

Then, Sir, I urge that one or two more trains should be introduced in that area. We are told that a number of passenger trains have been introducec from 1956-57. I hav been urging that a fast express train should be started from Bijapur $t$. Bangalore via Gadag-Hospet-Bellary and Guntakal. From 1956 when the States Reorganisation came .n, Mysore has become a bigger State, the Karnalak State. More areas have come in and more people are going towards Bangalore. But for thirteen hours there is not a single train betwern Gadag and Bengalore on this tine. There has been an agitation tor a long time; the traffic is increasing enormously and the equipment of the railways has also increased. I have been agitating for the introduction of this train.

I would in this connection just quote a few figures. The number of new trains introduced in 1956-57 was 119 on the broad gauge and 43 on the metre gauge; in 1957-58 it was 118 new trains on the broad gauge and 27 on the metre gauge; in 1959-60 it was 165 new trains on the broad gauge and 25 on the metre gauge; in 1960-61 it was 58 new trains on the broad gauge and 18 on the metre gauge. In 1956 when I asked for the introduction of a new train, I was informed that when the position with regard to the availability of locomotives and rolling slock improved, this question would be eonsidered. Hundreds of trains have been introduced in other areas. I do no: know why it has not been possible for Governmint to introduce this on train, though there is very great need for it

Mr. Deputy-Speaker: The hon Member's time is up

Shri T. Subramanyam: I will take only two more minutes.

After the reorganisation of States prop'e coming from the Karnatak areas of Hyderabad, Bumbay and from Bellary district have 10 go via Guntakal to Bangalore for various transactions and Government wo:k Many passengers coming fom that area have not been able to find accommodation at Guntakal to pioceed towards Bangalore. I suggest that some more carriages may be attached to the trains proceeding towards Bangalore.

Then, Sir, 1 was informed sometime back that an additional broad gauge line would be constructed between Guntakal and Hospet to enable iron ore to be exported to other countries. It is of the utmost importance. It fetches us a substantial amount of foreign exchange. The iron ore is of the richest variety and is in great demand in other countries. I, thercfor urge that this line should be constructed as early as possible. Track renewals and strengthening of bridges have to be taken up on the

Kottur-Hospet, Rayadrug-Bellary and Gadag-Sholapur and completed as early as possible.

I am glad there has been a reduction in the claims filed from year to year, but still Government had to pay Rs. $3 \cdot 13$ crores in 1958-59 and Rs. $3 \cdot 74$ crores in 1959-60. Lakhs of claims are being fled from year to year. I hope Government will take adequate steps to min!...ise this.

Mr. Deputy-Speaker: The grievances which are being voiced are mostly local in character and hope that can be done within ten minutes. I would request hon. Members to condense their remarks so that a larger number of hon. Members may be accommodated. Naturally there is a desire this time on the part of many Members to speak.

Shri Kalika Singh (Azamgarh): Sir. the Railways are the biggest of the public utility undertakings in India and they are said to be the fourth largest network in the whole of the world. It is, therefore, the responsibility of the Government to see that they are run most efficienctly, more particularly becaure they are directly connected with the progress of our Five Year Plans. At the commeacement of the first Five Year Plan it was thought that railways were not very essential; so no money was provided in the First Draft Outline which was presented to Parliament. Later on a sum of Rs 200 crores was provided: at the end of the Plan, however, it was found that a sum of Rs. 423 crores had actually been apent on the railways. So, the railways spent Rs. 200 over and above the amount alloted to them. So it was the progress of the Plan that ahowed that the Railways are very easential and the planners were wrong.

In the Second Five Year Plan, therefore, a sum of Rs. 1,125 crores had been provided for the rallways. At the end of the Plan we see that the whole of this sum has been utilised,

## [Shri Kalika Singh]

although the other Departments were not able to utilise the whole of the sum allotted to them. In the case of the railways only an amount of Rs. 4 crores remained unutilised; that is they spent Rs. 1,121 crores.

The Railways are very essential to meet the transport requirements of the country. The investment on this public utility undertaking is Rs. 1,732 crores. With this investment we should see that the ralways are run very efficiently. We have also to see that the foreign aid available to the railways is more than to other public undertakings or developmental works. The World Bank has been from time to time advancing loans because the capital at charge is substantial and the railways have got a very big asset. The International Development Association has also come into being and I think more and more money will be available from that Association apart from the World Bank. With the amount alloted in the Third Five Year Plan, the railways would be able to complete their planned programme with the result that the transport requirements of foodgrains, coal, steel and other essential items would be met very efficiently.

There is one thing I have noticed. It is that the working expenses have gone very high. In 1938-39, the gross earnings were Rs. 107 crores and the working expenses Rs. 71 crores, but in 1958-59, the gross earnings rose to Rs. 392 crores and the working expenses to Rs. 324 crores. The increase in the gross earnings during this period was nearly 366 per cent, but that in the working expenses was 456 per cent. If the gross earnings increase, the working expenses should also increase, but not more than the rate of increase in the gross earnings. But as I have just now shown, the increase in working expenses has been 100 per cent more than the increase in gross earnings.

Thea I have noticed that there is a b 'g increase in the number of staff. The figures given in Indian Railways (1959-60), Table XVIII, show that in 1938-39, the number of Class I and II staff was 1,784 , but in $1959-60$, it rose to 4,408. As regards Class III (a) employees, that is, those employees who were receiving more than Rs. 250 per month, tie number in 1938-39 was 7,602 , but in 1959-60, it rose to 23,866 . The strength of Class IV employees has not increased so much in Class IV, there are twegories, (a) and (b). In category (it), the increase is from 98,000 to $1,81,319$. These figures are for 1951-52 and 1959-60. In the (b) category, the figures for the same period are $4.92,856$ and $5,09,653$.

So the increase in Class IV employees might be taken to be 100 per cent or even less, but the increase in the case of Class I, II and III (a) is more than $400-500$ per cent. So the working expenses have gone up very high and the pattern of employment aliso during these years shows that the higher class offfers have increased in number more than the lower class of officers. The operational efficiency of the railways has to be judged by the performance of those persons who really work the lines on the spot. If there is an increase in their number, efficiency will certainly improve. But if we go on increasing the staff in the offices who do not actually operate the lines, that might not be so much conducive to the promotion of efficiency of railways. Therefore, it has to be discouraged.

As regards passenger earnings, the earnings from air-conditioned coaches in 1959-60 was Rs. 1.18 lakhs, from first-class Rs. 8.06 lakhs and third class Rs. $1,11,90$ lakhs. Here atso, we have to see that we provide more amenities to the third class passengers. But overcrowding has been going on and we have seen on railways, particularly in the metre gauge, that there is a lot of overcrowding eapecially
when there is mela traffic. We just cannot bear the sight of a train in the metre gauge when there is mela traffic.

Shri M. B. Thakore: In the summer season also.

Shri Kalika Singh: People travel on the roof of the trains and accidents have taken place. Instead of providing more trains and more coaches on the lines, the authorities advise pilgrims not to travel. If people want to travel and visit places of pilgrimage, the railways should provide the necessary travel facilities rather than discourage them. I think the railways do not actually want people to stop travelling to pilgrim centres; they only want to avoid the responsibility that may be fastened on them when passengers fall down from trains or other accidents take place. Therefore. they only give a warning.

There is one more point, a very important one. This is concerning Moghalsarai. It is stated:

> "The daily werage 110 ments in he direction above Moghalsarai was 1,687 wagons compared to the previous year's figure of 1,661 and the movements reached a record figure in September 1959 when a daily average number of 2,002 wagons were moved through Moghalsarai compared with the previous, year's record of 1,792 wagons".

Moghalsarai represents the biggest bottleneck in transport in the whole of India. Coal and other goods wagons passing through Moghalsarai come from Bengal-Bihar collieries. Now one alternative line is being provided. Garhwa-Robertsganj, to divert some of the wagons, but in view of the increasing number of wagons, it is stated that by the end of the Third Five Year Plan, the number of wagons that will be passing through this bottleneck might rise even up to $\mathbf{6 , 0 0 0}$ Then I think one alternative line.

Garhwa-Robertsganj will not be enough. So I propose that a bridge should be constructed at Ghazipur. This has already been examined by the railways. The Research Institute at Poona has also, I learn, reported that the bridge is feasible at that point. So the Ghazipur railway bridge should be constructed and the line from Dildarnagar to Nagsar should pass over Ghazipur, and then it should pass from Azamgarh to Akbarpur or straight from Ghazipur to Zafrabad, which is only 60 miles. That will be a second alternative to transport all the coal wagons avoiding the Moghalsarai point.

I want to thank the Railway Ministry for one thing. For two or three years we had been demanding that the track between Mau and Shahganj should be renewed. It has been there ever since 1907, and was not renewed. Now it is being renewed at a cost of Rs. 50 lakhs. I have been told that now the trains there on the metre gauge will be running at a speed of more than 35 miles inmead of at the present rate of 15 miles. For that I thank the Ministry.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir. this is discrimination.

Mr. Depaty-Speaker: I should have given perference to those whose track have not been renewed

Shri D. C. Sharma: His track has been renewed.

Shri Aurobindo Ghosal (Uluberia): 1 had no intention of mentioning issues already discussed, but some of them are so pressing that they require emphasizing.

First, I will refer to catering, which has been already refer- $c$ to by m: hon friend Shri Braj Raj Singh The quantity, quality and the price of the fond supplied by the contractors . . .
ghri M. Thakere: It is departmental now.

Shri Aurobindo Ghosal: ...differs from station to station and from contractor to contractor. We know that some standard has been laid down, but in practice this differs. I request the hon. Minister to see if inspectors can be appointed to check the quality, quantity and the price of the meals that are supplied by the contractors.

As regards the meals supplied by the restaurant car of the railways, the price of the items is increasing daily, and it has almost reached a prohibitive limit. So, I request the hon. Minister to see if the profit element can be reduced on the meals supplied in the restaurant cars to passengers.

Regarding the three-tier system, most of the Members have pointed out the difficulties. I would like to suggest one thing. Previously, in the three-tier classes, they used to supply some chairs, one-seat chairs. These used to be left vacant on one side for the sitting of persons who do not like to sleep for some time at night, but these chairs have also been now converted into berths. What happens? During day time the passengers of the middle berths have got to sit on their seat: with their luggages on their laps. Therefore, either you must retain the old system of providing chairs on one side, or at least you should keep the upper berth vacant for keeping luggage. This is my suggestion regarding the three-tier system.

Regarding the suburban trains of the South-Eastern Railway, in the last 20 years the passenger traffic has increased by about 400 per cent, but the trains have increased by only two. The total number of up and down sub-urban trains in 1940 was 46: in 1951 it was 44 and in 1959 it was 48, but during this time passenger traffic has increased by about $\mathbf{4 0 0}$ per cent.

Secondly, not only is there overcrowding, but the runnine time has heen extended too much. The running time has been increased by about 50 per cent. Previously the 16 or 17
miles used to be covered in one hour by the local trains. Now it is being covered in one hour and 20 minutes. 1 would request the hon. Minister to see that the speed is increased and the running time of the local trains reduced on the suburban side of the SouthEastern Railway.

Now I come to the trade apprentices of Kharagpur. In Kharagpur, about three years ago several hundreds of these apprentices were trained, but only a few of them have been absorbc.d. Even today, about 200 trade apprentices and carriage apprentices who have received training at the cost of the railways have been kept unabsorbed. I do not think in any other zone of the railways, such skilled halds to whom training has been given at the cost of the railways are being kept unemployed. I would request the Minister to consider giving employment to these carriage and trade apprentices of Kharagpur.

Yesterday, a news item has appeared to the effect that in the North Fastern Frontier Railway, in 1959 about 200 young men were declared fit for getting work by the Railway Service Commission, but none of them has been absorbed yet. The difficulty is this, that the Employment Exchange also does not allow them to register their names, because they have been approved by the Railway Service Commission, but they are not getting absorbed in the railways either. So, that point also should be considered by the hon. Minister.

Another point to which I would like to refer, which is very important, is that the railway yards of Chitpur and Shalimar are being used as underground commodity markets. In the first week of February, it has appeared in the papers that the hon. Deputy Minister, Shri S. V. Ramaswamy, visited the railway yards of New Delhi and found huge quantities of coal and frewood heaped there, and they were not released by the business men in order to create artificial scar-
city in the market, becares: of the low whariage rate. What happens in Calcutta is this. All the rape seeds are sold from the Chitpur yard. About 35 lakhs maunds of mustard seed are imported mainly from Bihar and U.P. Daily, the Delhi market opens in the morning and the prices are fixed in Calcutta towards the afternoon. In the Chitpur yard the rape seed bags are kept ' $n$ the wagons. they are not released. There, underground market is run in the yard on the railway receipt itself, and that is being allowed. The real market, the producers' market, is in Howrah, but the goods are to be taken delivery from the Chitpur yard. The sample of the goods which are shown in the market. in the Rail bazar of Howrah, are not the same or similar to those delivered from the Chitpur yard. This sort of corruption is being allowed, and in all the newspapers of West Bengal this has come out that underground share market is being run in the Chitpur railway yard and Shalimar godown. This should be checked. On 28th February, 36 wagons of mustard seed had arrived in Calcutta, but on that very day the price of mustard oil was increased by Rs. 20 a maund. It is inconceivable. In one day the price of mustard oil was increased by Rs. 20 a maund, though on that very day 36 wagons had been received in Chitpur yard. That is because the share market is being alloted to be operated in the railway yard itself. It is being operated on railway receipt without rcleasing the goods. That has to be checked.

The other day it has come in the newspapers that there was a pitched battle between the Railway Protec. tion Force and the people of the Rail. way Works Inspectorate in Shalimar. in which about seven persons have been seriously injured. The persons of the Railway Works Inspectorate were taking out goods from the rail. way precincts which was opposed by the Railway Protection Force, and there was a pitched battle between them. This is going on and the all
the small enginearing firtories of Howrah are run by the smuggling of lailway goods. So many lorries have leen scized by the Police on the G.T. Road when the railway goods have been so taken away by these smugglers. Naturally, more care shouid be taken to check these corrupt things.

Then, I would jike to mention about the D.S.T. staff-the District Signalling and Telecommunication Engineering staff. This office was in Garden Reach ever since 1936. After the strike, they were informed that this office would be transferred to Madhyd Pradesh. When there was a row, it was changed and they were given the assurance that the office would not be shifted. But. again, hardly a month has passed, the office has been shifted to Chakradharpur. Some of those employees who were given an assurance by the previous officers that their scrvices in any case shall not be transferred from Garden Reach to Chakratharpur have all of a sudden beer: transferred to that place. I would like the hon Minister to consider the cases of these persons

Then, I would like to refer to the case of railway employees. There nus been much discussion on the necessity for high operational efficiency in.d many hon. Members have suggested co-ordination between the differert Ministries in the matter of wagons and other thinga. But one point that: has been overlooked is that rea: operational efficiency depends upon the employces who keep the whule thing moving.

The hon. Minister in reply to the general discussion has assured us hat there would be no victimisation and that the cases of those 500 employees whose cases are atill pending and who are still out of service will be cor.sidered favourably. Stili, yenterday 1 have received - telegram that one of the Secretaries at Garden Reach has been victimised. Though that askurance has given by the Railway Minister, still there is victimisation

## [Shri Aurobindo Ghosal]

going on there in the Railways. Therefore, I would request the hon. Minister to see that further victimisation does not take place.

Next, there is the question of the Light Railways. It had been stated by the hon. Min'ster that as the agreement exists between the Distric Board and the Light Railway it is not poss:ble for them to nationalise the Railway. If that is so, I would ask, 'Is it the policy of Government to nationalise Railways or not?'. I would like the hon. Minister to consider this point.

There is the Howrah-Amta Light Railway which is run by Martin \& Co. If you do not want to take the responsibility of nationalising this Railway, then you should allow them to extend their services. The people of thoie areas have been demanding a line from Santragachi to Bistupur via Arambagh for the last 10 years. Government is refusing to accept that demand. Naturally, if you do not accept the responsibility of taking a new line, why do you not allow this Light Railway to do it-if they want to extend the line to those places via Munshirbat Penro.

We are being told that Government does not want that these Light Ralways should exist and that they are not going to extend these operations. If they are not in a position to take these new lines to these places then let them give permission to the Light Railway to extend their railway line to those places where government is not willing to take new lines.

Lastly. I would refer to the case of the retired railway personnel. personnel who have already retired and who are entitled to get benefits with retrospective effect as their claims have already been admitted ns just by the Railway Board. I would request the hon. Minister to consider these cases.

F nally, I would congratulate the hon. Minister that he has been able to keep himself away from the contamination of the hon. Finance Minister who has imposed taxes on whatever is fomed in heaven and on earth in order to make our life a hell.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Sir, I would like to make only a few observations. The Railway success has to be judged, in my opinion, not so much by the amount of contribution it makes to the General Revenue; as by the amount of facilitics it gives for growing traffic in men and goods. Though the Railwa;s are a commercial concern, the matter of concern is not only the profit it makes bu the convenience of the entire Indian puble who are also interested in it as taxpayers. So, there is a good deal of importance attaching to that aspect.

The other aspect of the Railways is that it is a source of developing the couitry. As a public utility concern also it is equally important. And. from that point of view, the scope which the Railways have been able to give to the trade and traffic in men and goods is also a matter which has to be counted as one of the cr teria to judge the real success of the Railways.

Many of the hon. Members who havi. preceded me today and other days also in the general debate have pointed out the shortage of wagons everywhere. I also want to bring that point to your particular notice. In fact. the hon. Ra'lway Minis'er, in his speech, also admitted that they are making great efforts to cope with the increasing traffc and yet they have not been able to give suffic ent numbers of wagons to the trade which is growing now.

I have brought to the notice of the Railway Mn'stry the complaint about the shortage of wagons at particular stations, Nagpur and Itwari, on the complaint made by the timber merchants of those places. A question
was also tabled by me. Unfortunately, the question could not be accepted as a Starred Question because for the date on which I wanted the answer the whole list was full and so it was treated as an Unstarred Question. The reply that was given to me only stated that every effort is being made to step up loading to the maximum extent possible within the availability of wagons. It is not a bad reply; it is hopeful. I have nothing to say about the language of the reply. But that does not solve the difficulty of those who have complained.

I would draw attention particularly to the fact that the timber merchants have been complaining about the shortage of wagons at Itwari and Nagpur stations for the last 3 months. The total wagons required on 8th January, 1961 were 63 . Further additions to the requirement for the period 9th January 1961 to 27th February, 1961 was 39 . The total requirement was, therefore, 102. As against this, the number of wagons supplied prior to 31st December, 1960 is only 25 . So, I am told that there is a great shortage of wagons. Wagons are yet to be allotted although indents for them is accepted in January. So, after making necessary additions and sub-tractions, the total number of wagons required against which indents are not being accepted is 66. This complaint has been there for nearly some months together. You can imagine what amount of loss it would mean to the timber merchants to allow their stock to lie there without being allowed to be sent to the proper destinations in proper time.

The Railways may have their own difficulties. But I want to say that the Railways must see to it that they invite traffic. If that is not done there are others who are doing itand they are our brethern too. But we will be losing a good deal of profit which ought to be earned by the Railways because. I attach ereat importance to the Railways particu-
larly for carrying heavy goods. If that capacity of the Railways is not improving there would be much cause for complaint by the people. I hope that this will be duly noticed by the Railway Department and something will be done to look into the grievances of the timber merchants. The association had been sending representation after representation to the Chief Operating Superintendent, Central Railway and copies of these are being duly supplied to the hon. Railway Minister.

Now, I want to bring to the notice of the Railway authorities the point which I have been thinking for many years. When I was here in the old Legislative Assembly, we tried to make some improvement of railway communications in Vidarbha and the Maharashtra part adjacent to Vidarbha. Among the improvements which we succeeded in making was the construction of a narrow-gauge line from Darwha to Pusad. Now, later on, when the first War came, this line was among those that were to be dismantled when this matter was brought to the notice of the authorities they said that they would not dismantled this line and if at all it had to be dismantled, it would be done after certain further facts were ascertained. But the line was removed without the notice of the railway authorities. These things will be found in the old records if the hon. Minister goes through them. I have got the old correspondence with me. But then a speciffc promise was given that when dismantled lines were taken up for restoration, this would be one of the first. After that fortunately circumstances changed and the War was over and new lines were taken up for construction. I was not here then but was lying ill at Poona. I sent telegrams to our hon. Priend, Shri Lal Bahadur Ehiastri, who was for some time in charge of the Railways, about this line. Till lately the matter was under consideration and I have been recently told that the matter had been abandoned altogether. I put a epecifc

## [Dr. M. S. Aney]

question but that could not come up and 80 it was treated as an unstarred question and I found that the answer was that it was an unremunerative line. I want to ask this question. Are they relying upon some old records made by the old railway agent?
Have they really made any new enquiries? I am in a position to prove that it is not only not unremunerative but it is more remunerative than many other lines sanctioned. They should not take it up as a matter which has been finally decided but should keep it under consideration till they find out the facts.

There is one more point. At that time among the lines that were sanctioned was the Khandwa-Hingoli line also. The survey was made and this line had come up but the line from Narkhed to Amravati was not taken up as the retrenchment policy came in and we find that the matter has been abandoned. Efforts should be made to look into the old records and they should find out whether it is not worthwhile to take up that line. The district through which it has to pass -Amravati-is one of the most fertile districts of Vidarbha. So, it will be a payng proposition.

There is one more suggestion and I shall conclude. Thousands of pilgrims go every year to Badri Narain and Kedar Nath. If there be hili stations, Government does not mind spending money for construction lines to those places and connecting them by railways.

> The Deputy Minimer of Rallways (Shri 8. V. Ramaswamy): Their sanctity will be lost.

Dr. M. S. Aney: There are many people who thing that it is worthwhile going there and if they reach there, the sanctity, if lost will be reatored. These are religious places. Just like tourist places. They should be made attractive and accesstble to people. Every Hindu
believes that it is as meritorious to help a pilgrim to a holy shrine as to make the pilgrimage himself. If sins are made in laying the line, the sins will be washed away by a dip in the Ganges there. These are the principal matters. About other matters, I shall correspond with the Railway department.

Shri Nanjappan (Nilgiris): Sir, I was pleased to note that the Railwary Minister announced on the floor of this House more than once that the railway line on the west coast which is needed will be laid. Sir, the west coast which is needed will be laid. Sir, the west coast is well-connected by sea, air and also by road. The national highways are laying a road on the west coast and the Railway Minister was very right in saying that there should be a railway line on the west coast. In fact, there is a metre gauge railway extending from Punjab in the north to Kerala in the south. Recently, by laying the line between Hingoli and Khandwa, the metre gauge was connected from north to south and a link between north and south established. But there is yet a break of metre gauge in the south. That line has to be laid. Long ago, this line was recommended by both the Mysore and the Madras Governments. But it was not taken into consideration and so that matter was lying idle. For various reasons, this line is important, and so, both the Governments recommended that this line should be taken up. Yet, nothing was done, though the Rallway Minister promised that a west coast railway line would be soon laid. This break is between Chamarajanagar in Mysore State and Coimbatore in Madras State. It is a distance of about 80 miles. If this line is laid, I think a direct railway line could be obtained from Trivandrum in the south to Punjab in the north, through a metre gauge along the west coast.

It was men'ioned that roads rum parallel to railways in Madras State. It is not a apecial feature of Madras

State. Roads run parallel to railway lines in other States also. For instance, there is a road from Delhi to Agra and it also runs parallel to the railway line, and the railways also are putting up a number of overbridges so that the traffic on the roads may not be unnecessarily hindered. In fact, the railway lines were laid parallel to the roads everywhere. So, to say that roads are parallel to railway lines . only in certain parts of the country is not correct. Such a feature does not hinder the railways in anyway from carrying goods. That was admitted by the Railway Minister himself in his reply to the debate on the railway budget. There will be no competition between the railways and the roads.

Again, mention was made about the losses in the Southern Railway. That is not a special feature of the Southern Railway only. After all, the route mileage covered by the Southern Railway in the Madras State is only one-sixth of its total route mileage under its jurisdiction.

The next point that I would like to mention is about the third class travel. The Railway Minister announced in this House as well as in the other House that there would be no relief from overcrowding in third class coaches. That may be so, but by saying so, he also means that he is not in a position to ask the railways to carry all the passengers who want to travel third class. That is not my point. My specific point is about the real overcrowding in a third class coach. What do the railways do to prevent this overcrowding? How does this overcrowding come about? They issue more tickets than the accommodation wartants. They put up in bold letters, "To seat $45^{\prime \prime}$ or whatever be the number. But they issue as many tickets as are demanded and so the overcrowding is there. The railways complain about ticketless travel, but by issuing more tickets than the seats warrant. they voluntarily encourage the ticketless travel. So, by limiting the num-
ber of tickets to be issued, as they do in the case of upper classes, they could prevent overcrowding in third class coaches, and thus avoid the present inhuman conditions of travel in third class compartments especially in the case of passengers travelling long distances.

There is also a question of principle or legality in regard to this matter. That is, a bus cannot take more than the prescribed number of passengers. The driver cannot take even one passenger extra, whereas the railways allow as many passengers as are offering themselves for travel, even though the railways have mentioned that there is accommodation for such and such number of passengers only. They must give consideration to this aspect and see that only the prescribed number of passengers, especially in the case of long distance passengers, should travel, and not more.
The next point I would like to mention is about the seat. While the Railway Minister was pleased to take Her Majesty the Queen to the Integral Coach Factory at Madras, the Queen remarked that the third class seats would be very hard for the passengers to sit. We can imagine the people travelling hundreds of miles in these coaches, sitting on such hard seats. The railways have provided many amenities to third class passengers, and so why not they provide softer seats in third class coaches? Even if such an amenity costs a little more, 1 think the fare can be increased, and the long distance traveller will be quite willing to pay more.

The Railway Minister wan saying that he would be abolishing the second class. I mention this, because by abolishing the second class, more accommodation will be available to the third class passengers even without soft seats.
[Bais Jnonkatia Rao in the Chatr]
Apart from that, if a softer seat is provided and if a limited number of

## [Shri Nanjappan]

people alone are allowed in the third class, the second class can be totally aboished in the interests of third class passengers.

One more point which I would like to make is regarding the air-conditioned coaches. Air-conditioned coaches are attached even to the trains which run only short distances. For instance, to trains running from Bangalore to Madras or from Madras to Coimbatore, air-conditioned coaches are attached. After all, the distance is very short and the nights on these routes are fairly cool, and there is no need for air-conditioned coaches in these trains. Why I am mentioning this is because I am told that these air-conditioned coaches are so heavy that in their place two third class coaches can be added. If that is so, why should there be these air-conditioned coaches in short distance trains? By attaching air-conditioned coaches to these trains, not only is the third class traveller affected but even the first class traveller is affected on those days when the air-conditioned coaches are put in. The number of seats are less in these coaches and the passenger suffers. Not only that: reservation at intermediate stations is also not permissible, and to that extent also, the passenger suffers.

The next point I would touch upon is catering. Here again, the Railway Minister was very much pleased to say that the food supplied by the railway department is very good and that departmental catering is going to be resorted to more and more. I am glad about it. But the quality of lood, especially the South Indian vegetarian food, is very poor. The rice water is thrown out; so also, the water in which the vegetables are boiled is also thrown out. So, the nutrition is lost. Mere plantain curry or some cheap tubers are supplied. Formerly they used to give dal separately, but that is not to be seen nowadays. What we get to gulp some rice with is some tamarind solu-
tion called sambar or rasam. Ghee is very little and the butter milk or curd is not good. So, my submission is that the South Indian vergetarian food that is supplied should have some calorie value and it should be a balanced diet. The railways should see that they supply a balanced diet which has some calorie in it and also some nutrition.

## 14 hrs .

Regarding the sanitation as_ pect of the way in which the food is supplied, it is not done in a sanitary way at all. There must be some principle in doing these things. As a traveller, I can say that the plates are being carried by oue man. Formerly there used to be two plates, but now all the plates are heaped up one above the other without any covering. What actually happens is the bottom of the upper plate touches the food in the plate below and it is all exposed. They bring it in that way. This sort of catering is not at all good and it cannot be said to be sanitary. So many times one can find foreign matters also in the food.

My suggestion is, just as they have trained men for so many purposes, for catering and cooking also, people should be taken and given training. If that is done, better food can be supplied and better sanitation can be maintained. Not only the food supplied is not in a sanitary condition, but the station yards also are in a bad condition. If you see Howrah station, for example, it is in such an unsanitary condition. Sanitation must be improved and I hope the railway authorities will apply their mind to it.

बी घासर (रल्लागिरि) : मभापति महोदय, रेलबे की की हिमाष्ट्स पर जो बहस हो रही है, उसमें बोलने का डो मापने मुले घबसर प्रबान किया है. उसके सिए में घापको घन्यबाद देता हूं। मेंने इन डिमाण्ड्य पर कुष्ष कटटती प्रस्ताब पेश किये हैं घोर उनमे से कुष्ब पर में बोसना काहता है।

सबसे पहले मुझे बम्बई की सुवर्वन लोकल रेलवे के बारे में कहना है। बम्बई को भाबादी दिन-र्रति-दिन बढ़ती जा रही है। हाल हो में जो सेंसस दुरा उसके फलस्वसूप भ्रापको पता चल जाएगा कि वहां की प्राबादी $x \gamma$ लाख तक जा पहुंची है मोर जो रेल क्यषस्था है, वह इन सभी लोगो की जसरतों को पूरा करने में सवंया भ्रसमर्यं सिद्ध हो रही है। इसका परिं णाम यह होता है कि जो लोकल ट्रेंस हैं, वे हमेशा ही लेट हो जाया करती हैं . . . . .

रेलषे उपमंश्री (की घाहलेखाज बता): भाबादी को रोकना चरहिये।

धी चासर : भाबादी जब रकेगी तब छकेगी लेकिन जो बढ़ चुकी है उमके लिए तो भ्रापको कुष न कुष्ध प्रबन्ष करना ही होगा।

में कह रहा था कि नोकल ट्रेन्स जो हैं वे हमेशा ही लेट हो जाती हैं फोर दो दो या चार चार fमनट नहीं भाष भाष षंटे लेट पहुंबती हैं। इस का पfग्णाम यह होता है कि जो कर्मंबारी हैं वे पाफिस लेट वहुंचते हैं भौर उन को थनिष्घापूवंक भाषे दिन की दृट्टी लेनी पह़ जाती है । इस बढ़ी हुई धाबादी को देसते हुए भोर साथ ही साथ तो छंख्ट्र्री वहां बढ़ रही है उस को देलते हुए वहां की रेल-क्यवस्था में कुष्ष मुषार करना भावद्यक हो गया हैं। इस के लिये कुष विशोष म्यवस्था की जानी चाहिये ताक्ष स्थिरति में सुषार हो । में भाप को धपने घनुमव से बतलाता हूं कि ? मार्चं को में पूना जा रहा था मोर बम्बई से जो हो क्रन एक्सप्रेस हूटती हैं उस में में बंठा हुफा वा। बह गाड़ी मस्बिदबंदर क्षा कर एक बटा तक बकी रही। जब हम ने पूष्षा कि गाड़ी क्यों रक गई हों तो हमें जबाब दिया गया कि सिगनल नही हुपा हैं। जब हम ने पूष्षा कि सिगनस क्यों नहीं हुपा है तो जबाब भिसा कि द्रकिक बहुत्ता बक गया हो इस बास्ते घकसर गाष़्यां लेट हो खानी हैं।

हर दूसरे तीसरे दिन बहु थीज हेंती रहीीं। बहाँ पर ट्रेंस को घाष घंटा, घंटा रकना पड़ता है । इस के बारे में भाप को भावष्यक उपाय करने होंगे। बहां के यानियों को भाबए्यक सुविषायें काप को पहुंचानी होंगी। सूक भाबादी बछ रही हैं पोर साष ही साष इंस्ट्र्रीज भी वहां नई नई बालू हो रही हैं, उन की पावष्यकताषयों की पूरित करना पाप का कत्तंक्य है । वहां ओो स्टेशान हैं वे मी पुराने हो गये हैं मौर वे मुसाफिरों की जल्रतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। जब भाप स्टेशनों में मुषार कर रहे हैं तो भाप का उषर भी ध्यान जाना काहिये । बहां पर जो ब्बोटे घोटे स्टंशन हैं वे बेंसे के बंसे ही हैं। उन को बदलना पावश्यक ही मीर जहां पर इस समय स्टेशान नहीं है परर बहां पर स्टेशन की भावएयकता है, वहां भाप को नया स्टेशान बनाना होगा ।

भब में पोवर-fषिजिज के बारे में कुछ कहना बाहता हूं। पारले, पंषेंी मोर मालाउ स्टेशनों पर पोबर-जिजिए का होना बहुत भावर्यक हों। इन की घ्यकस्था न होने के कारण ट्रेफिक भाष भाष मोर पोन पोन बंटे तक रका रहता है। में पाशा करता मूं कि इस दोर धाप ध्यान वेंगे मोर बहा पर घोबर fिजिज की व्यवस्था कर वेंगे। बम्बाई के गो मुबबंन एfर्याज हैं, बहा पर जहा जहा भी पोवर fिजिए की भाबह्यकता हो, य बनाय जाने चालियें ताकि द्रफिक न हरने पाय ।

पूना पोर सोनाबला के मोगों की एक माण है जिस की तरफ़ में भाप का ध्याल दिकाना घाहता हूं। पूना एक बहुन बत़ा इंस्द्रियल टाउन है मीर लोनाषला वक बत़ी बत़ी सेन्ट्रीज बत़ी हों गही है। बहा पर भार्यनेस केष्ट्री लोर fर्मालद्री है्यो है। बद्दां की बनता की मांग हैं कि लोनाबला पूना सेक्सान को मी बम्बई मुव्रंन सक्नान के ममान हीं मुब्रंन क्षेखणन माना जाय। इस का पर्य पद्र होगा कि तो किराया बर्बाई
[细 घांसर]
सुपर्षन एरियाज में लिये जाते हैं, वही किराये पूना से लोनावला तक लिये जायें । यहां भी यह लोकल ट्रेन है। जिस तरह से यहां की माबादी बढ़ रही है, उस को दे खते हुए उन की इस मांग को ग्वीकार करना प्राप के लिये मुरिकल नहीं होना चाहिये । में चाहता हूं कि इस प्रोर विशोष हूप से घ्यान दिया जाय जब भ्राप बम्बर्ह में कम कि,गया लेते हैं म्रोर वहां के लोगों को विशेष महूलियतें देते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि वही महूलियतें प्राप पूना वालों को न दें। बहां पर नई नई इंड्ट्रीज सार्त हो गही हैं भ्रोग श्राबादी भी बढ़ती जा रही है, इस दृवि से उन की इस मांग पर सहानुर्भात से विचार करना भ्रावर्यक है।

भब मृक्जे पूना-fमगज-कोलहापुर लाइन के बारे में कुछ बहहना है। वहां की मीटर गेज लाइन को बदलाने का हम प्रयत्न कर ग्टे हैं लेकि.न भभी तक कुष्ध नहीं किया गया हैं । मंनी महोदय भी हर माल जब बजट घ्राता है तो इम को बाह गेज में बदलने का मंकेत करते हैं। तीन चार वर्यं से एूसा ही होता प्रा रहा है । लेक्न पभी तक कुछ्द नही किया गया है। प्रथम योजना ममाप्त हो गई, वृतीय समाप्त हो गई हैं, लेकिन इस बारे में कोई ठोस कद. नम नही उठाया गया है । भाज भी हम ब्बेलते हैं कि मवं के लिये कुष रकम रली गई है लेक्न उससे सन्तोष होने वाला नहीं है। हर साल यह नीज पाती है लेकिम हुप्य प्रगति होती हो, एसा दिसाई नहीं देता है। मं चाहता हूं कि मंरी महोदय इस के बारे में कुघ ठोस कदम उठाय ताकि लोगों को सन्तोष हो सके। कोलहापुर एक ईँ स्ट्टियस एरिया है, जहां पर बड़ी बरी ईंस्ट्रीज है, थागर कंब्ट्रीज है, हूती कपप़े की \{मसें हैं। सागली, माप्रनगर, कराए़, ीीरा, सतारा ये समी क्षेत्र ऐसे हैं जोकि तिजारत के सैटर है, संचस्ट्रमस एनि्याज हैं, मोर बहा से माल पराखहलन की उवित म्पसस्षा क होने के कारण बहुत असुकिषा होती है। याषियों

को लाने से जाने की घच्छी क्यवस्था न होने कें कारण भी काफी भ्रन्तोष वहां पाया जाता है। इन दोनों वृष्टियों से यह भावर्यक है कि इस मीटर गेज को बाउत्गेज में बदल दिया जाय । में पाशा करता हूं कि शीघ ही इस भोर घ्यान दिया जायगा।

प्रब मैं नई लाइनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस के मामले में महाराष्ट्र के साय बड़ा भ्रन्याय किया गया हैं, एसा में मानता हूं । महाराप्ट्र सरकार ने नई लाइनों के बारे में जो मूची ग्रेलवे मंत्रालय को भेजी है, उस में से केवल एक रेलवे लाइन की स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है। बजट स्पीच में माननीय मंत्री जी ने दीवा-पानबेल का ही जिक किया है प्रोर वहां ही एक नई लाइन की बात कही है। चूंकि महाराप्ट्र की भ्राबादी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है पोर वहां पर इंड्ट्टीज भी बढ़ती बा रही हैं, इस वास्ते जो भी सूची महाराष्ट्र सरकार ने भ्राप के पाम भेजी है, उस की घोर घ्यान दिया जाना बहुत पावष्यक है। मभी तक ऐसा नहीं किया गया है। हमारे मंत्री जी ने कहा है कि पिसहे हुए इलाकों को भागे बढ़ाया जाना जाहिये । माननीय मंत्रो जी समझते हं कि हस दीवा-पनबेल लाइन से कोंकन का विकास हो सकेगा। लेकिन माननीय मंती बी को पता नहीं है कि पनबे T नक्षो में कहां है। पनवेल बम्बई का एक च्रुप्यंन एरिया माना जाना हैं। पनबेल में रेल होने से कोंकम का विकास नहीं होगा। कोष्ल का विकास होना पावस्यक है फोर इस पृध्टि से पनषेल से रेल को विपलून तक बफ़ाता भाकरयक्ष है। यह केवस ६०-७० मील का एक टृकत़ा है। यहां पर रेल का होना भर्यषिक धाषषलक्र ह1 जब पाप ने पनवेल से लाइन विध्याने का निमंय किया हो तो पाप उस ते पारे बदिये थोर हस को जितनून तक बहाइये। बिपसून के पास ही कोयना प्रोजेष्ट है वहा से किजली मिसने बानी है, वहां एक्ष बत्र

का कारलाना ख्युलने वाला है, पेषर फेष्ट्री हीने वाली है, भौर छोटी मोटी इंस्ट्रीज होने वाली हैं, इस दृष्टि से वहां पर रेलवे का जाना पावरयक है। मैं घाहता हूं कि रेलबे मंश्रालय की तरफ से पनवेलखिपलून लाइन के लिये पावशावासन दिया जाय ।

दूसरी बात मैं रिटायरं रेलवे कमबारियों के बारे में कहना चाहता हहं। उहहोंने रेलबे मंत्रालय को भ्रपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। लेफिन उन की बात नहीं सुनी गई । मुक्षको ऐसा लगता है कि उन की बात पर सहानुभूति से विचार किया जाना चर्चाहिये क्योंकि भाज रिटायडं गेलवे कमंचारियों की हालत बहुत बराब है। सन् $९$ १४७ की जो पहीली पे कमिगन की र्पिोटं यी उस में उन की पेंगन के बारे में जो कुष्ब दिया गया था उस पर विजार नहीं किया गया । सन् $P Q ४ \cup$ के बाद पँशन देने पर विचार किया गया, लेकिन उन को पता नहीं था। जब मन् $P e^{\gamma} ง$ में वे थमिशान ने इस बारे में सिफार्का की तो सन् $९$ ह४७ से पेंशन की यह योजना क्यों नहीं चालू की गई । चूकि बाद में की गई इसीवये यह प्रयल्न किया जाना घाहिये कि fिटायं रेलवे कमंबारियों को मी उस का मुनाफा मिले ।

स्पीह के बारे में एक या दो बाते बतलानी मावश्यक हैं । यहां पर भ्रक्सर सीह की कर्षा होती है। हमारे यहां हेकान अवीन है यह पहले पूना से बम्बई बाई बटो में आया करती बी लेकिन पष उस को मा⿳े तीन या पोने बार षटे लग जाते हैं। केटियर मेल को जो पहले साढ़ें २२ घटे लगा करते बे थब उस में २义 बटे सगते हैं। परिक, हम पीषे की दोर क्यों जा के हें ? उबनि कया उमाना का रहा है तो हमारी रेखों की जो स्सीट वहोे बी उस में दोर कमी हो रही है, पह ठीक नहीं है। इस्सिये जो हमारी मेल ट्रेने या एवस्पेत्ट ट्रेने हैं उन की स्वीड को बताने का प्रयल किया बाय।

ऐकिसिेंट्स के बारे में मी में कहना आहता हू। विशोषकर जो ऐस्सीरेंट विद्षले बार सः दिन में हुपा उस की कर्षा मैं करणा बाहता है। उस के पहले जो ऐकिस्सरेंट हुणा वह तो चलती गाड़ी में हुभा था, उस की बात तो छोड़िये, बम्बई हावड़ा एक्म्र्रेस बड़ी थी, नागपुर स्टेशान पर उस पर दूसरी ट्रेन क्षा कर टकरा गई । उस में ६३ पेसेन्जर घायल हुए। वैसे ही स्थिथि जो एक्सिरेंट परसों हुप्षा उस में हुई । रेलवे स्टेशान पर गाड़ी खड़ी थी, दूसरी गाड़ी ने घा कर उस में टवकर दी। उस में १२ पादमी मर गये मोर कुम्द घायन हो गये। भाबिर इस तरह के टेक्षिस्टेंट्म की क्या वजह है ? क्या वहां पर कोई पोटंर नहीं होना जोकि गाड़ी के लढ़े होने का माइन बतला सके? लत़ी गाड़ियों के साथ एविसडेंट्य होना बड़ी बतरनाक बात है, इर्मलिये इम तरफ घ्यान दिया जाय।

यहां पर रेलवे केटारंग के बारे में कुष्ष कहा गया। हमारे एक भाई ने फहा कि फू बहुन बराब मिलता है, किर भी خेलष केटटरिग सब जगह् बसाई जाय। जो लोग कुम्य मुली हैं उन को भी दृष्यी करना बाहते है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जब प्राबवेट केटरिग बलती थी तो मोलों को पच्छी तरह में क्षाना मिलना था मोर पष कुछ ठीक था । पब हम ने कृष आगढों वर रेलबे के हाथों में उमे दे विया है। किषाटंमेंटक्र किटरिंग होने के बाद पनाज जो मिलना है वह बहत्त बराब मिलता है मीर दाम ज्यादा वेगा पऱन्ता है। इस स्पिति को देबते हु हुमारा केटरिश क्जिरमेंट जो षठठ हुा है उस सिम्टम को ब्वलना बाहिये। उस में कर्पाल बहुत है, किजा कर्प्णन के ाम तर्यु की बातें नहीं हो मकनी हैं। पह्ये प्राईंेट को उस से मुनाफा fिनका था होर पष्क्ष घनात मी सोगों को भिमता था । मेकिन जात्र हा में जाटा हो गा है। मे गेलबे मंत्राबय से प्रार्यका कस्का कि क्रम बारे में दूरी बोल बीय
[ल्री भासर]
की जाय घ्रोर श्रगर हम इस काम को हीक से नहीं कर सकते तो इस को घोड़ दिया जाय घोर जो पाइवेट केटरिंग करने वाले है उन के हाथ में इसे दे दिया जाय ।

भाखिर में में रेलवे डिपाटंमेंट की चोरियों के बारे में कहना चाहता हूं । इन घोरियों में कोई कमी नहीं हुई है। हम ने स्पेशाल रेलवे रिजर्व पुलिस रख दिया, घौर इस के पर चखर्चं भी किया, लेकिन ग्राज तक इस के बारे में कोई कमी नहीं हुई । में ने पिद्घले साल प्रशन पूछे थे । दीवा एक स्टेशन है जोकि चोरियों का घड्डा है। वहां रात मौर दिन का कोई सवाल नहीं है, बराबर रात दिन रेलवे का माल चोरी जाता है । पता नहीं लगता कि रेलवे डिपाटंमेंट भ्रोर रिजवं पुलिस सो गया है या क्या हुभ्रा है । लेकिन यह जरूर है कि इस को कोई रोक नहीं सका है। में तो समक्षता हूं कि इस में हमारे भफसर शामिल है, घोर यही कारण है कि पूना घोर कल्याण स्टेशन यांड चोरियों के मह्डे बन गये हैं। हस चीज को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

की श० स० तिबारी (खजुराहो) : सभापति महोदय, भभी दो तिन दिन से रेलवे की बहस चल रही है। इस में घधिकतर यह कहा गया है कि रेलवे के काम में बड़ी शिाथिलता है। इस के बारे में में यह बतला छेना चाहता हूं कि रेलवे ने दूसरी योजना में जिस तरह से काम किया है वह सराहनीय है। इस योजना में रेलवे ने सब से बड़ा काम यहृ किया है कि जो भीड़ भाड़ घलती थी उस को कंट्रोल करने के लिये २३ परसेन्ट गाड़िया धोर घलाईं। इसलिये भाज भी भीक्ष तो होती है, लेकिन उतनी नहीं हैंजितनी पहले होती थी । दूसरा काम जो रेलवे ोे किया है वह यह है कि पहासे कसस, दूसरे कसास धौंर तीसरे क्सास के कर्मचारियों के पर्मांत भवकाश के समय को, ? घप्रैल,

सन् १६४७ को जो श्रार्डर जारी हुप्रा था उस के घ्रनुसार एक लेवेल पर ला दिया है। दोनों ही के लिये भ्रब एक सा समय कर दिया गया है। तीसरी बात जो रेलवे विभाग ने किया है वह यह है कि ? ६ नवम्बर, १ह४७ को यह तय किया कि रेलवे के सभी कर्मचारियों को फ्रब पेंशन मिला करेगी । यह्र एक बहुत बड़ा काम किया गया है। चोया सब से बड़ा काम उन का यह है कि भ्रगस्त, १eप₹ में वेतन कमिशान ने जो रिपोर्ट दी थी उस में जो कुछ कहा गया था उस को करीब करीब रेलवे विभाग ने मान लिया है, जिस में $१ ३$ करोड़ रु० सालाना से ज्यादा का खरं भ्रायेगा। यह काम थोड़े नहीं हैं। किटिसिज्म करना भ्रासान है परन्तु वास्तविकता को देखना चाहिये । हां यह जरूर है कि जितना काम होना चाहिये था उतना नहीं हो सका है हालांक वह काम होना भावर्यक था ।

सब से पह्ली बात तो यह मैं निबेदन कलंगा कि घ्राज जो हमारी रेलवे में भामदनी बढ़ती नहीं दिसाई देती । उस का एक कारण यह्ह है कि भ्राजाद हिन्दुस्तान घीरे धीरे उठ रहा है जिस की वजह से सेवायें बढ़ती जा रही है, लेकिन उस बढ़े हुए खचं का मुकाबला करने के लिये रेलवे की घ्रामदनी बढ़ाई जानी चाहिये जोकि नहीं बढ़ रही है । हमारी बसेज का जो काम चल रहा है यह भविष्य में रेलवे के लिये एक खतरा साबित होगा । इसलिये उस की सीमा नियत की जानी घाहिये । सब से बड़ी जो शिकायत हैम को पाप से है वह् यहि कि बहुत सी रियासतों को मिला फर भ्राप ने बड़े बह़े प्रदेश बनाये हैं, जसे कि मध्य प्रदेश है। एक मध्य प्रदेश में ही $\gamma_{0}, x_{0}$ या ६० रियासतें मिलाई गई हैं, जोकि छोटी छोटी रियासतें बीं । उन रियासतों में रेल तब भी नहीं थी घोर घब भी जब हमारे मंत्री महोदय रेलों की प्लैनिग करते हैं तो उन का ध्यान क्ष की तरफ नहीं जाता कि पिधरे़े हुए इसाके हैं, जैसेकि

बुंदेलखंड, उन को लिया जाय। भ्राप बुंदेलबंड में कहीं पर रेल नहीं पायेंगे ६०, ७० मील इषर उषर । हब से बड़ी बात जो में प्राप के सामने रखना चाहता हूं वह है यह् कि सीषी जिला में सिगरोली एक तहसील है, जहां पर \&०० वर्ग मील में कोयले के लिये सर्वेक्षण किया गया । वहां पर बहुत ज्यादा कोयना है, लेकिन रेलों का कोई प्रबन्ष नहीं है, जबकि गुजरात के बारे में यह खबर है कि वहां फल कारखाने बन्द होने वाले हैं क्योंकि कोयला नहीं पहुंचता है। इस लिये मेरा निवेदन है कि सिगरोली से रीवां तक सीषी रेल लाइन बनाई जाय जोकि रीवां, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर होती हुई सीषे गुजरात तक पहुंच सकती है । इस से भाप को कोई ३०० मील लम्बी रेल लाइन निकालनी पह़ेगी जर्बक घ्राज 400 मील चल कर गुजरात में पहुंचना पड़ता है। इस तरह से बीना भोर गुना को भी एक रेल लाइन मिल आयेगी। इसलिये में चाहता हूं कि यह रेल लाइन बनाई जाय क्योंकि इस से बुदेलसंड्टा की शिकायत भी दूर हो जाती है मोर सिगरोली से एक सीषी लाइन भी मिल जायेगी जहा पर छतना कोयला है कि घगर भाप $१ \frac{1}{\text { या }}$ २० साल भी लें तो भी सत्म नहीं होगी ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि बहुत से जिले रेलबे से कनेक्टेठ नहीं हैं। उन के बारे में मेरा निवेदन है कि वहां पर कम से कम पाउट एर्जेसी ही बना दी जाय जिस से कि माल के भाने जाने में सहूलियत हो जाय ।

बहुत से माल पर रेलबे को नुकसान पूरा कर्ना पड़ता है । लेकिन जो नुकसान करने के लिये जिम्मेबार होता है उस को नहीं पकड़ा जाता । घगर एेंता किया जाय तो मै। सममता हूं कि नुकसान बहुत कम होने सगे सेकिन ऐष्षा नहीं होता ।
(F). जहां तक मास की ड़लाई का सम्बन्ब है बहुत सी बीलें तो सीषी द्रकों से बसी आती है, माप के लिये बषता ही क्या है, रेसबे से

सड़ने गलने बाली चीयें, जैसे फल, साग भाजी मोर तम्बाकू घादि भेजी जाती हैं जिन का किराया कम है मोर जो जगह ज्यादा लेती हैं। यही चीजें पाप को मिलती हैं। उस में भी बिल्ली के फल वालों को शिकायत है कि नागुर से जो संतरे घाते हैं उन को घाने में सात दिन लग जाते हैं। यह सड़ने वाली चीज है मौर घतने समय में बराब हो जती हैं। ए के लिये पषिक सुविषा मिलनी काहिये।

मेरे यही हिदूस्थान में पान सबसे ज्याषा होता है। हरपालपुर भोर महोग्रा से पान लदता है, ले किन जिस दिन वह पाता है उस दिन नहीं लादा जाता, द्रसरे दिन लादा जाता है। कभी कभी तो वह दोपहर में षूप में पड़ा रहता है। भोर यहां भाने पर सड़ जाता है पोर फेकना पड़ता है। लोगों ने मब रेलब के बजाय सीषे ट्रक से पान लाना घुएँ कर दिया है पोर वह उसी दिन यहा वहुंब जाता है। यदि इन छोटी छोटी चीजों की पोर घ्यान न दिया गया तो रेलबं का मल का ट्रेफिक सल हो जायगा ।

पाप ने जो केटरिंग में भोजन की घ्यवस्था की है वह संतोषअनक नहीं है । मेंे साथी भभी उस की धिकायत कर रहे षे कि वह सन्तोषजनक नहीं भोर उस को प्राइवेट कर दिया जाय। जब यह क्यबस्था प्राइबट हायों में थो तो जिकायत की जाती बी मोर कहा जाता था कि सरकार इस को भपन हाप में से ले । लेकिन इनना तो जहरी हुं कि कुद्य तोल निधिबन कर दो जाये । भभी जो बार खपातियां देने हैं ब तोन में एक घटांक भी नहीं हांती हैं। तो कुग्न गोल रलें पाब मर में या प्राषा पाब में जार बागातियां बनायी जाय । कुआ विमिट ग्लनी जिएये ।

थी कालनखाँ जा : लिमिट है।
थी हा० ल० Iलाती : नेकिन उस पर भ्रमस नहीं होता। इस पर भी ज्याल

## [श्री रा० स० तिवारी]

बेता चाहिये । मं चाहता हूं कि मेम्बर पार्लयायामट भी इस चीज को बेसे पौर इस की शिकायत मंत्री महोवय से करें ।

भ्रांसी से मानकपुर जो लाइन जाती है उस में कोई तेज चलने वाली गाड़ी नहीं हैं। सब धीमी चलन वाली गाड़ियां हैं। घ्रोर फिर उन में लदान भी होता है। इस के हर स्टे गन पर ब लेट हो जाती हैं। एक बार में न प्राथंना की थी प्रोर प्रांडर हुप्रा था कि इस लाइन पर एक एकस्रे्रेस गाड़ी चलायी जायगी, लेकिन फिर कहा गया कि उस लाइन के पुल कमजोर हैं, इसलिय भारी इंजन उन पर नहीं चल सकते हैं मेग निवेदन हैं कि भगर पुल कमजोर है तो उन को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाय ताकि यहां यातायात की मुविषा हो सके।

में एक योर निवेदन करना चाहता हूं । जो पिद्घड़े हुए प्रदेश हैं पोर जो रियासतों से बनाये गये हैं उन के लिये प्राप कम से कम यहु करें कि गो पुरानी पटरी है उस को हालें पोर जो पुगने हिब्वे मोर ₹ंजन हैं उन को जोड़ कर एक रेल बना दे ताकि कुछ कमी पूरी हो। ह्म लोग मभी उसी में संतोष कर सिगें । भाप को सिफं ट्रेंक बनाने का खर्व करना पड़ेगा, बाकी तो वही सामान होगा जो कि प्राप रदी में नीलाम कर देते हैं।

एक मानवीय सकस्य : एक्सीउंटंटे लिये जिद्मेदार कौन होगा ।

- ती रा० न० किजारी : पहले तो मास डोया जायेगा, किर जब पंसेंजर बले तो एक्सीरेंट का सबाल पंषा होगा ।

मेरा निवेषन है कि उन स्थानों पर जास घ्यान दिया जाय जहां कि भभी रे ल नहीं है। बहां भगर रेले बनायी जाय तो पच्छा होगा 1

8hri Kodiyaa (Quilon-Reserved8ch. Castes): Mr. Chairman, Sir,
though I have moved a number of cut motions on various subjects, I wiah to confine myself to the demands of the peopla of Kerala with regard to rail travel.

Mr. Chairman: Only ten minutes are allowed.

Shri Kodiyan: Only ten minutes?
First of all I shall refer to the need for opening some new lines in Kerala. I do agree with and support the view taken by the Railway Ministry that in opening new lines preference should be given to those lines which will serve the industrial centres and mining areas. But importance should also be given to areas which are economically and industrially backward because opening of new lines there will, to a very large extent, facilitate the growth of new industries, trade and commerce in these areas. Viewed in this background Kerala needs special consideration.

I find that a sum of Rs. 120 crores have been provided for opening new lines during the Third Five-Year Plan period, but not a single pie has been allotted for opening of new lines in the south. Several hon. Members from the south. who have spoken, have already referred to this aspect.

Coming to Kerala, the Kerala Government have suggested some seven or eight new lines to be taken up in Kerala. We have demanded these lines not merely for the convenience of passengers but also for the reason that for the movement of goods also these new lines should be undertaken in Kerala. I do not want to mention all the lines proposed by the Kerala Government, but I should mention a few lines. The Tellicherry-CoorgMysore railway line was approved by the Ministry. This line was even surveyed in 1955. But so far no action has been taken. I do not know why no action has been taken and whether this has been dropped. I want an explanation about that from the hon. Minister.

Then there is another line which was surveyed even before the Telli-cherry-Coorg-Mysore line was surveyed, that is, the Trichur-Kollengode line. That also seems to have been abandened now. The Tellicherry-Coorg-Mysore line, if constructed, will be the only line that will connect Kerala with Mysore.

Then there is another line proposed by the Kerala Government, namely, the Kayamkulam-Ernakulam line via Alleppy. Alleppy is an important industrial centre on the west coast and goods from the Alleppy area will have to be moved by country boats. It will take much time and it is too expensive also. If a line is constructed via Alleppy connecting Kayamkulam with Ernakulam, it will facilitate the development of this coastal area.

Then the Trivandrum-Cape Comorin line is a very important line. The hon. Deputy Minister, Shri Ramaswamy, also, I think, has once expressed himself in favour of opening that line. But nothing has been done so far

There is a proposal to have a chord line in my constituency connecting Punalur on the Quilon-Shencotta line with either Mavelikkara or Chenganoor or Thiruvalla. This will also help the hill produce to be brought to Cochin Harbour.

Then I come to another point, namely , that of the capacity of the existing lines. The line connecting Cochin Harbour with Shoranur was constructed many years ago. Since then, Cochin Harbour has developed and traffic has also increased considerably. Due to the limited capacity of this line there is a lot of trouble in Cochin Harbour. The main reasons for demurrage on goods in Cochin Harbour is this limited capacity of this line. Goods are being held up there because they cannot be cleared due to the insufficient capacity of this line. As far back as 1952 the Cochin Port authorities had requested the Railway Board to double this track between Cochin Harbour and Shoranur but nothing has been done so far. I do
not know whether there is any proposel for doubling this track during the Third Five-Year Plan period.

So many hon. Members have referred to the problem of overcrourding apecially in the third-class cuaches. The hon. Railway Minister has thia time also, as in previous years, stated that the problem of overcrowding will remain there for the next few years also. I do agree that with the limited number of coaches and rolling stock it may not be possible to eliminate overcrowding completely in the near future. But something has to be done where overcrowding has become the greatest problem. For instance, with regard to the main trains that run between Kerala and Madras, whether it be the Mangalore Mail or the Cochin Express or the Trivandrum Express, the problem of overcrowding is very acute. It will be very difficult to get accommodation from Madras in these trains to Kerala. Last year I had the experience of travelling in a third class compartment of the Cochin Express-I did not get accommodation either in first or second class. In that compartment I could sit up to Coimbatore, but from Coimbatore onwards I could not even sit, because from all the important stations from Coimbatore onwards poeple began to come and crowd the compartment. So it was difficult even to sit. This was my own personal experience.

Then, the train that runs between Mangalore and Cochin Harbour is always crowded, whether it is coming from Cochin Harbour or going to Cochin Harbour. Recently I read in a local newspaper a statement by an ex-Minister who had occasion to pull the alarm chain to stop this traln. In order to get a seat he had entrained from Cochin Harbour. Af'er four or five stations the compartment got so overcrowded by people from the wayside stations that he felt-he says in his statement-that the passengers inside the compartment would be suffocated to death, and so he had to pull the alarm chain. The guard came and told him that he was helplese,
[Shri Kodiyan]
because from every station-as Shri Nanjappan informed the House just now-tickets were issued indiscriminately to all the passengers who came for tickets. Such is the state of affairs there. I would, therefore, request the hon. Minister to run an additional train between Mangalore and Cochin.

Then, Sir, I am glad to find that the hon. the Railway Minister is paying more attention to the third-class passengers, and sleeping coaches have recently been introduced on various routes. Sleeping accommodation has been provided in one train in Kerala also, that is in the Mangalore Mail. But practically this is of no use, because this accommodation is provided only for passengers travelling over 700 kilometres. That means only those passengers who would travel to the farthest end of that route from Madras to Mangalore, will get this accommodation.

Shri Shahnawaz Khan: It is available for everybody.

Shri Kodiyan: No, it is not zvailable.

Shri Shahnawaz Khan: It is available if you pay for it.

Shri Kodiyap: That is true. Every passenger to Kerala, whatever be his destination, has to spend a night in the train before the train reaches the borders of Kerala. I would, therefore, requst the hon. Minister to introduce these sleeping coaches in other trains also, that is in the Cochin Express and Trivandrum Express. All the passengers who travel more than 500 kilometres should be given this sleeping accommodation without any additional payment.

You will be surprised to find that most of the main railway stations in Kerala have no retiring nooms. And you will be further surprised to find that even at the railway station at a divisional headquarters, like Olavakkot, there is no retiring room facility.

Cannanore, Ernakulam, Quilon, Calicut, all these are very important stations; they are always crowded and there is heavy traffic, but there are no retiring rooms at these places.

Then there is the question of overbridges. We have put in this very House several questions about these overbridges. But I find that in a place like Shoranur, where a lot of shunting $i_{s}$ also being done, there is no overbridge. Normally, if a train is coming, one will have to wait for half an hour where there is no overbridge. But at Shoranur you will have to wait for more than one hour if there is shunting also. That is the state there. Similarly, there are some other places also where overbridges have to be constructed. These things require the attention of the Railway Ministry. I request the hon. Minister to look into these grievances and take necessary action.

पंधित छा० का० लिबारी (केसरिया) : सभापति महोदय, मुक्षे रेलवेज की हिमांड्स पर कई बाते निवेदन करनी हैं लेकिन में चूंकि भापकी घंटी से ठरता हू हसलिये कम ही बात कहंगा। इसलिये कृपया घंटी जरा देर से बजाइयेगा क्योंकि में तो उसको पूरी तोर से मानने बाला हूं

सभापति महोबय : दस मिनट का समय है ।

पंगित्त बा० ना० fिबारी : ठीक है जैसी भापकी भागा।

इस रेलवे बजट को देखने से पता चलता है कि रेलबेज की चारों घोर प्रगति हुई है। सब घोर कुष्ब न कुछ प्रगति हुई दृषि्टगोचर होती है इसलिये रेलवे मंच्री महांदय को बहुत बषाइयां भी मिली है है

में घुर में रेलबे मिनिस्टर साहष को कह्ट देना चाहता हूं कि उनको यह भाष्वासन देना जाहता हूं कि में किसी यीज की मांग करने के लिये स सड़ा नहीं हुपा हू क्योंक में

जानता हूं कि उसको देना उनके हाय में नहीं है । भ्रब भगर में नई लाइन्स की मांग कहां तो वह पहले प्लानिंग कमिशान में जाएगी पौर न मालृम म्रोर कहां-कहां घूम कर जाएगी घौर तब जाकर कहीं वह चीज होगी। नई लाइन को देना यह उनके हाय में नहीं है। लेकिन में उन चीजों के बारे में जो कि उनके हाय में है भौर जिसकी कि वजह् से रेलवेज की बदनामी होती है घोर उसकी प्रगति में बाधा पड़ती है, जिक्र करने चला हूं भौर में चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन खराबियों को दूर कर दें।

सबसे पहली भ्रावशयकता किसी भी क्यापार या कर्मशायल सविस के सफलतापूवंक चलने की यह है कि उसका स्टाफ सैटिसफाइड हो । में समझता हूं कि मंत्री महोदय इसमें मुआसे सहमत होंगे कि रेलवेज के स्टाफ में भगर कुस लोग भी डिटरर्मिड डिस्सिटिसफाइड हों तो वह मापके काम में बाषा पहुंचाते हैं। भ्रब रेलवे कमंचारियों में भ्रसन्तोष होने के मामूली-मामूली कारण रहते हैं। कमंचारियों से कोई उनके भ्रफसर रंज हो गये नाराज हो गये घौर वे भफसर महाशय भ्रपने उन कमंकारियों का रिकां खराब करने लगे घौर उनको नुक्सान करने की तलाश में रहते है घोर किसी दूसरे कसूर में उनको हटा दिया जाता है। बे बेचारे प्रपनी करियाद हेकर हमारे पास माते हैं। हम लोग इंहिविजुम्रल केसेज मापके सामने लाने में ठरते हैं घौर बह़त कम केसेज मापके सामने लाते हैं। भाज हालत यहु है कि उन को ग्रीवियांसेज के दुछस्त होने में काफी समय लग जाता हैं घोर जिसका कि नतीजा यह्ह होता है कि उन बेबारों की जितनी भी दूडी जमा होती है बह सब पषर से उषर दोड़ने में छरं हो आती हैं। इसलिए में घाहना हूं कि रेलबे बोर्ह इस घोर घ्यान दे मीर उनके प्रोवियान्हेज जल्ती से बल्दी दूर करने की व्यबस्था करे। उनमें ब्राज जितना समय नहीं लगना बाहिये । मुत्षे ऐसे केसेत्र का इल्म है जो कि पिद्धे पार्व बजों दे पॉं० है हौर बे बेारे विल्मी, मोरा-

पुर मौर पटना दौड़ते फिरते हैं। पगर मंशी महोदय इसके लिए उदाहरण चाहें तो में उनके सामन कई उदाहरण रख सकता हूं।

भब यह जो हड़ताल हुई थी वह् केषल महीना बढ़ाने के कारण ही नहीं हुई थो बस्कि उसमें घौर भी बहुत से छोटे छोटे ग्री बियन्सेज भी शामिल थे। जिनसे कि स्ट्राइक की नोबत घाई घौर मेरा कहना है कि उ $f$ बोटे-बोटे ग्रीवियान्सेज को दूर करने से पापका काम प्रासानी से चल सकता है ।

दूसरी बात यह है कि रेलतेज जब बनाई गई थी तो उस समय में प्राबादी भी कम थी घोर जिन लोगों ने उसको बनाया था उन्हें जनता की मुविषा देखने की गरज भी नहीं थो। उन्होंने एट रं ब्म जहां चाहा लेविस कांसग दे दी कहीं पर तो एक-एक मील पर लेविल कासिग है घोर कहीं चार, चार मील पर भी रोविल कासिग नहीं कें। भब भाज पह़ले की पपेक्षा घाबादी भी बहुत घषिए बढ़ गयी हैं मौर गांव भी बढ़ गए हैं यह भाबइयक हो गया है कि लेवस काॅंग पषिक बनाए जाएं । मब इमके लिए यह् कहा जा सकता हैं कि नये लेबिल कोमग तो तभी बनाए जा मकते हैं जब गांब वासे वंसा हें या स्टेट गवनंमेंट पंसा दे लेकिन मेरा कहना यहु है कि जिस बक्त यहु बनते घे उस समय भगर कोई समम्पेविटिक मरकार होती तो एटरंब्रम न बना कर बलिक एक व्यबस्थित भाषार पर लेषिल कामिग्स घोर स्टेशन्म उसने बनाये होते। मुले मालूम हुं कि बाग से पोपासमहोता के बीच में चार मील तक कोई केषिल कांमि नहीं हैं। इस मम्बन्ब में सिकने पर यह कहा जाता हैं कि रेलबज का स्व यहे हैं कि पहिने बं जमा कीजिये, या स्टेट गवर्नेंटेट से जमा कराइए। धक्तर यहु मी देखा आता है कि कहीं-下रंत तो एक माइस में दो-बो मेविल एकिंग है हीर कहींकही चार माइल तक एक भी नही बेत हैं। मैं यह निबेयन करना चाहता हूं कि यहा रेलये प्रशाबन की ज्याबती हैं बीर उसको इस कोर
[रंड्ति ज्ञा० ना० विवारा] ध्याम दे कर लोगों को सुविषा देने का प्र गत्न करना बाहिये ।

हम वेबते हैं कि रेलये प्रोटेक्शान कोरं के हीते हुए भी गाडियों में बोरिया होती हैं मोर रेलबे की कीरें जाती हैं। उनको कोन प्रोटैक्ट करेगा ? पालिर रेलवे प्रतेक्रान कासं कित लिये है। में समझता हूं कि रेलवे का कोई भी सामान बिन रेलवे कमंबारयों की कनाईवेंस या एक्टिव को-्रापरेशान के ضोरी नहीं हो सकता है। इसालये भावएयकता (स बात्र की है कि रेलबे प्रोटैष्यान फोसं को स प्ररह भ्रागंनाइज किष। जाये कि हमारी नेशनल प्रापर्टी बरबाब न हो सके।

कुछ्घ लोग तो सामान षोरी करते हैं, लेकिन रेलवे बोटं टाइूम की चोरी करता है। غे हटील टाइम । भ्राप जरा पांच छः बरस वहले के टाइम टेबिल पोर प्राज के टाइम टे बिल में तुलना कीजिये पोर देखिये कि टाइम में कितनी बोगी हु है। एक माननीप सदस्य ने कहा है कि एक्मप्र्रस २२ धंटे के बजाय भ्रब २२ घंटे में चलती है। यह टाइम की बोरी है। यह् तीन घंटे रेलवे विभाग ने हमारे ले लिये हैं । रानग टाइम को बक़ा दिया गया है मोर कः जाता है कि गाड़ियां पंबनुमल हैं। क्यों हैं ? में ने इसको स्कूटनाहज किया कि रांनग टाइम बब गया है पोर कहीं-कहीं घतना स्टोपैज हो गया है कि यदि गाड़ी लेट भी हो आये, तो भी बह मेक्रप कर सकती है। रेलवे प्रशासन को पस प्रकार की क्यबस्पा करनी चाहिये कि लम्बी याशा करने बाले व्वाक्ति सफर से ऊब न जायें भोर उनका बहुता समय बरवाव न हो। पहलेे पटना से दिंसी बीस बंटे में जाते ये फोर पब बाइस घटे में 1 हसी प्रकार वहोे गोरसपुर से घ्घपर जाने में पाष बंटे सगते पे, जू कि घब सात, घाठ बंटे लगते हैं मैने $\mathbf{~ ह स ~ स म ् ब ल ् ष ~ म े ं ~ ए क ~ र े ल व े ~ ह ा ल ा ~ ध ा क ि त र ~}$ से पूष्षा मीर मुक्षे बताया गया कि घगर मापको ठीक समय दिया जाता, तो जाप को स्टेशक पर के क्रा पस्ता । पष भाप घतमीभाज

से स्टेक्षन पर मा सकले हैं। भष ज्वासा टाइम दे दिवा गवा है मोर भाप स्ट्रान के खजाये घर पर बेठ सकते है ? उस में क्या हानि है ? यहु जबाब बुन कर में मबाल् रह गया ।

जहां पर रेलवे विभाग को एपरोष रोश्ज बनानी हैं-स्टेट गवनंमेंट को नहीं, वहां पर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। एपरोष रोश्ज्ज इतनी बराब हैं कि उन पर बंलगा़ी़ी भी चलना मुरिकल है । हमारे किप्टी मिनिस्टर साहब बड़े एनच्पूजिएस्टिक हैं । वह एन०ई० रेलबे में मा कर एपरोब रोट्स को बेलें ।

भी जाहनवाज लों : जो एप्रोच रोड्ज स्टेशन की हुद्दूद के प्रन्दर हैं, उनके लिए ही हमारी जिम्मेदारी है ।

वंशित त्ञ० ना० तिवारो : मं उन्हीं की बात कह रहा हैं। जो लाइन से उतर कर फाटक के भीत्रर हैं, में उनके सम्बन्ध में ही निवेदन कर रहा हूं 1 क्वाटर्गे केषिय्य में हम जानते हैं कि प्रभी वे बन कर मुकम्मल नहीं हुए हैं कि चने लग गये हैं। ग़्रोंच रोड्ज के लिए भेसा दिया जाता है, लेकिन वह कसे खर्ष किया जाता है पौर बे रोक्ज केंसे बनती हैं, यह में नहीं कह सकता।

इन घोटी-बोटी बातों पर में माननीय मंत्री महोदय का ऽयान इस लिये पाक्षाषत करना चाहता हूं कि वह इस तरफ तबज्जह दें। वह्ह बिना संवं किये इस को ठीक कर सकते हैं 1

भी घाहनकाल का : बगंर सर्ं के केसे ?

यकित ता० का० किजारी : प्रशु सर के पास ख्पया हैं होर वह प्राविगन करता है, लेकिस उसको ठीक तरह से संत्र नहीं किया जताता है, क्यया सेस्ट किया जाता है। एश्रोष रो्ञ्त के बिसे क्षा है वह सें होता है

या नहीं मोर उचित रूप से बरं होता है या नहीं, इस वरक तवज्जह करने की मावहयकाता है। इसी प्रकार ट्रैविल का टाइम बढ़ा दिया भया है। में नरीं समल पाता कि उस को ठोक करमे में क्या खरं है । स्टाक की किसी घ्यीस का फंसला करने के लिवं भी किसी लर्ष की जलरत्व नहीं है —सिफं तबम्जह की जल्रत है । पांच-्पांच बरस से केसिज लटके हुए है । या तो हमारी बुद्धि घौर हमारी भाषा ऐसी नहीं है कि हम उनको समक्षा सकें, वा वह ही समझ नहीं पा रहे हैं।

बी आहलवाज लो : में तो यह जानना चाहता था कि एश्रोच रोड्स कंसे बगंर बषं के बन जाती हैं ।

ध्री राजेन्त्र सिह (छपरा) : माननीय मंगी जी ने म्रगन उत्तर में क्रा है कि पहा पर एप्रोच रोड नहीं हैं, वहां पर रेलबे विभाग नहीं, बल्कि स्टेट गवनंमेंट प्रोवर-क्रिज बनायेगी, छपरा में, जहां से में भोर श्री तिवारी भाते हैं म्युनिसिर्ंलित्री की मोर से एपरोच रोड बनो हुई है, लेकिन फिड भी तीन बरस से मोवरक्रिज नहीं बना है ।

धी शाहनबाज लो: माननीय सदस्प की बारी भी भायगी ।

पंशित छा० ना० तिबारी : बहुत से माननीय सदस्पों ने कंटरिंग के बारे में कहा है। स्टेशन पर जो चीजें बेची जाती हैं, उनमें पान भी है : पान का दाम दो पेंसे रस दिया गया ह——ाहे केसा भी पान हो । हम पान साने बले हैं मोर हम जानते हैं कि कितना खराब पान मिलता है । पान में कोई नका भी नहीं है। प्रशासन घतना काम से लेता है कि बह उसको मैंनेज नहीं कर सकता है। जो काने की जींें स्वास्प्यवषंक हों, उनकी क्यबस्था तो बह बेशक करे, सेकिन पान, बी़़ी, सिगरेट का काम हेने से क्या कायदा है ?

बी साले fिह : एक की रिकेसमेंट स्म 日बी वरद तो करी चक द्वा है।
 मेरा ढाइम न लें ।

I am not making any demand. I am simply drawing your attention to those things, that they can do easily without any expenditure.

प्रब एक प्रोर समस्या की पोर में माननीय मंबी का ध्यान पाकषषत करना बाहता हूं। हम बेलते हैं कि दक्षिक में एक गांब है घौर उत्तर में गांव बासों की जमीन है जिनके बीब में बिलेज रोड है मौर अब रेलवे किभाग उस रोष को एकसमयर कर लेता है तो उन लोगों के लिये जाने का रास्ता नहीं रहता है। में पहाड़ीघक गांब का जो सोनपुर स्टेझन के निकट है उदाहरण वेना बाहता हां। बहां पर वक्षिण में कई गांब हैं बौर उन के होत है उसर में, घंर मकान है वकिण में 1 बीब में रेलवेज ने जमीन ले ली है । पब वे लोग केसे थांए जायें। उनका मामला कई बरस से चल रहा है। रेलबे विभाग ने वहां चारों तग़़ वीवार बना दी है। इससे उन लोगों को बहुत कठिनाई का साममा करना पड़ता है। माननीय मंती ती को इस समस्या की घोर मी ध्यान देना चाहिए।

पब मं यह बताना चाहता हूं कि एक लेबिल कासिग के तोन-तीन बंटे बन्द ग्हने से लोगों को बहुन कठिनाई होती थी। में ने हस सम्बन्ष में रेलबं fमनिस्टर साहब को प्रंम किया, तो घंबर किज एंमी जगह बना दिया गया कि बहां के लोवों को कोई फ़ायदा नहीं हुपा है। यदि उस को पूरं के बजाये परिसम में बना विया जता, तो लोगों को धबषय क्रायदा होला। मेरे कहाने का तात्पर्य यह है कि हुम ओो मुकाव देने हैं, उनको छस तरीक से एक्मीक्यूट किया जाता है कि उसमे मोगों को कोई फ़ायका नहीं होता है। यदि उस घोषर किज्य को उननी हो द्रा म्टंशन के परिख्य की तरक्र बमाषा आता, अितना कि वह वूर्ष की तरक्र बमावा क्या है, तो उसी
[वंधित ब्वा० ना० तिषारी]
संच से स्टाफ़ घौर गांव वालों दोनों का फ़ायदा हो जाता। भब मुना ह्ं कि वहां जो भ्रोवर क्रिज है, उसको भ्राइलेंह तक, सड़क तक ले जाने की बात है। में कहांगा कि उसको स्टेशान के परिचम में कर दीजिये थौर सबन्वं जो सड़क पर जाने के लिए बना है उसे कनेष्ट कर दीजिये तो ज्यादा भ्ष्छा होगा। उसमें बर्चा भापका ज्यादा नहीं पड़ेगा । इसी खर्चं में क्रापका काम घल जाएगा। प्रगर भापने ऐेसा नहीं किया तो गांव वालों का काम नहीं चलेगा प्रोर मुप्त में संक्षट खड़े होंगे । भरभी भी एक केस घल रहा है इसके बारे में । कई बार मंने पौर हमारे दोस्तों ने रिप्रिजंट किया है लेकिन कुष भी नहीं किया गया है । भाजकल हो क्या रहा है, छस पोर भाप ध्यान वें। नीचे से जब फाइल बलती है, क्लकं से जब फाइल कसती है तो बह जो नोट लिख देता है उसको कपर तक देबने वाला कोई नहीं है। कोई यह नहीं देलता हैं कि फाइल में क्या हैं पोर क्या नहीं हैं। उसी नोट पर भार्डर पास करते हुए चसे जाते हैं। में कहुंग कि इस को जरा ध्यान देकर देला जाए कि दूसरे लोग क्या जाहते हैं, केंसे उनको लाभ पहुंच सकता है ...

यी बाहलकाए को : फाइल वहां रहती है, लेकिन पारंर बदल जाते हैं।

पिित्ता० का० किजरी : नोट्स पर घाप भाडर देते हैं । पाप सोनपुर की फाइल को मंगा कर दे लिय, उसमें क्या है। वहां की गवर्नेंमेंट ने क्या लिला है, पुलिस ने क्या मिक्षा है, लोगों ने क्या लिक्षा है, गांव बालों ने क्षा लिला है। वहां पर जनरल मेनेजर ोेलने गए बे, हमारा उनके साष सम्पक्ष नहीं हो सका नहीं तो हम उनको बता देते कि किस कीज की दावर्यकता है।

वह जो टूवार्रस बेटर कमि््यांस थाफ द्रे०ल नामक पुस्तिका हमें ीी गई है इसके

पेज ३६, भाइटम नम्बर $\varepsilon$ में छ: स्टेशनों के नाम दिए गए हैं जहां फुट क्रिज या सब-वे बनने वाला है उसमें एक डिषवाड़ा स्टेडान भी है। इसके बारे में बहुत दिनों से लोगों की एक डिमांड चली भ्रा रही थी। मुझ्षे डर है कि इसको भी कहीं गलत बंग से न बना दिए जाए प्रोर जित्ता लाभ लोगों को होना चाहिये, उसके फलस्वरूप वह न हो मके। यहां पर भोवर-बिज की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि म्रंछरत्रिज की है । लाइन के दक्षिण में विलेज है । दक्षिण में उसके गॅजिज है । वहा उसका एक्सपशन नहीं किया जा सकता । दक्षिण में एक्सपेंशन की कोई गुजाइञ नहीं है । एक लिक रास्ता विटवीन स्टेशन एंड मालगोदाम हो जाए तो लोगों को फायदा हो सकता है, उनको पषिक सुविषा हो सकती है। लंकिन मुक्ष उर यह है कि प्रंडर क्रिज न बना करके कहीं भोवर-fिज बना दिया जाए प्रोर पषिचम न बना करके कहीं पूंवं बना दिया जाए ये सब चीज हैं जिनकी मोर भापका ध्यान जाना बाहिये। भापको बाहिये कि इन पर भाप विचार करें मोर जिसमें प्रषिक मुविषा हो वहीं काम करें ।

मैं कोई नई ₹िमांड पेश्र नहीं कर रहा हुं पोर न कोई ऐेसी ठिमांड्पेश कर रहा हूं जिसमें पषिक ठ गया लंखं हो। जितना भापका प्राविजन है, उसी को इस तरह से बरं करने की बात मैं कह रहा हूं जिससे जनता को पषिक लाभ हो सके। जिस तरह से मैने भापको काम करने के लिए कहा है भगर भापने उस तरह से उसको किया तो लोगों को संतोष होगा कोर बे धापकी जय जयकार करेगे ।

में बाशा करता हूं कि जो मुमाव मेंने दिए हैं, उन पर भाप बिभार करेंगे कोर जो कुष भाप कर सकते हैं, करने की कोसिस करेंगे । मेरे मुलायों में पषिक्र वंसा क्रतं करने की कोई

## बान नही है, इप वास्ते मैं श्राशा करता हूं कि ग्राप उनको स्वीकार कर लेंगे ।

Shri M. B. Thakore: I thank you yery much for giving me some time to speak on the Railway Demands. At the outset, I congratulate the Railway Administration for the excellent work that they have done.

Shri Rajendra Singh: Are you thinking of going over to the other side?

Shri M. B. Thakore: No, I shall never go. .

I unders and from the speech of the hon. Railway Minister that on account of political, economic and social reasons, Government have decided to construct new lines in the south. I would request the hon. Minister that on the same basis, he should consider the question of constructing railway lines, or. I would say. links in Gujarat.

In North Gujarat especially, Panchmahal. Dang, Surat, Navsari and Saurashtra areas are very backward; they are mostly backward and undeveloped. I would request the hon. Minister specially to construct a few lines there, because there is no transport facility nor any conveyance available there at the time of monsoon. North Gujarat is on the border with Pakistan, and if it is developed it will be most useful in the future.

In North Gujarat, there is a Kutch desert that is advancing towards the east, towards Banaskantha and Mehsasa districts. If the Railway line from Kandla to Palanpur is doubled, 1 think the area will slowly develop. and the Kutch desert also will be prevented from advancing. I spokt about this in 1959 in the course of the debate on the Railway Demands, but nothing has been done up fill now. At the las: meeting of the consultative committee. I was discussing this matter, when the han. Deputy Minister Shri S. V. Ramaswamy was there, and he wished that I should speak about
this on the railway budget. and he did not allow me to speak about these lines earlier. These links are not more than 7 miles in length, in any case, not more than 20 miles. The expenditure also will not be very much. I suggest that the following lines be constructed during the Third Five Year Plan. The first line is between Kherula or Vijapur to Himmatnagar. Then, there is a line up to Harij. If it is extended to Radhanpur via Sami, it will not be more than 20 miles. I do not think there is any river or any nullah where it would be necessary to build a bridge. Thirdly, I would suggest a line between Kakoshi to Sidhpur or Chhapi, which is only a distance of about six to seven miles. There is a great demand from all over these villages Kakoshi and Chhapi for this line. Then, fourthly, there is a line up to Vadnagar. From there, I would suggest the extension of the line via Sundhya, Ranchodpur, Unjha, Balisana to Patan. This is a link which is not more than 20 miles. I do not think there is any big river in between.

Then, there is need for a small link, which I always advocate, and that is from Tranga Hill to Timba. I have already written many times to the hon. Minister, because near Tranga Hill, there is a Jain temple, and many of the passengers or pilgrims go there. I think there are lines, but the trains do not go up to Timba; they go only up to Tranga Hill.

The second point that I want to make is regarding the imposition and collection of fine at Sidhpur railway station and other stations. I really wonder why there is no overbridge there. I have written on this matter many times. I have seen the General Manager and even the Minister talked about this in the consultative committee, but no steps have been taken about this foot overbridge. They say that they have written to the Gujarat Government, but there is no reply. Since 1957, the reply is the same. And in 1961 also, the reply is the same. and there is no change. I do not know

## [Shri M. B. Thakore]

whether the Central Government, especially the railways have sent any reminders to the State of Gujarat or not. The municipality is ready to construct the approach road, but there is no action taken regarding the foot overbridge up till now. In the absence of this overbridge, when the villagers pass from the station and cross the railway lines, they are caught there by the police and taken to the magistrate, probably first class, I do not know, who summarily tries and imposes a fine, and if these persons are not able to pay, they are sent to jail. I asked a question of the hon. Minister of Railways, but he has replied in the negative. I really wonder how he got that information. I have seen with my own eyes a person looking like a Magistrate imposing and collecting very heavy fine, Rs. 5 and Rs. 10, and if you argue, Rs. 20. I know that the First Class Magistrate of Sidhpur was also fined, and even he had to pay it.

## 15 hrs .

Shri Shahnawaz Khan: Did he trave: without ticket?

Shri M. B. Thakore: There was no question of travelling. He was crossing. There is the Sidhpur mill and other mills and villages are on the other side of the station.

Shri Narasimhan (Krishnagiri): So it was trespass.

Shri M. B. Thakore: Yes, may be.
Shri Narasimhan: Running the risk of being run over.

Shri M. B. Thakore: As I told you, even a First Class Magistrate was fined. Since very long, there was no foot overbridge there.

Mr. Chairman: He was fined not because he was a Magistrate.
Stri M. B. Thakore: He crossed over.

Mr. Chalrama: He committed an offence.

Shri M. B. Thakore: My hon. friend, Shri Shahnawaz Khan, denied that there was imposition and collection of any tax.

Mr. Chairman: It is not a tax.
Shri S. V Ramaswamy: It is a fine, not a tax.

Shri M. B. Thakore: Yes, fine. You may refer to unstarred question No. 1317.

Shri Narasimhan: Kindly read the question and answer.

Shri M. B. Thakore: The question was:
(a)" whether it is a fact that heavy fine is imposed on the ignorant and innocent villagers and others who cross the railway station at Sidhpur and other stations on the Western Railway on the plea that they have no platform passes or tickets with them; and
(b) "if so, the total fine collectc.d during 1959-60 and the number of persons sent to jail in this connection"?

Shri Shahnawaz Khan, the Deputy Minister, answered:
(a) "No.
(b) Does not arises".

According to him. there was no imposition of fine.

Shri Narasimhan: Let him raise a half-hour discussion on it.

Shri M. B. Thakore: The second point I would like to make is regarding some servants of the canteen contractors at Ambliyasan and Kalol. In this regard. I met Shri Shahnawaz Khan and the General Manager so many times, but they did not listen to me. It is the ruling of the Speaker that if there are diffculties in regard to administrative details, we must write to the Minister or see him. That was why I saw htm so many times. But unfortunately no steps have been taken. I
spoke about this in the Railway Budget discussion of 1959，and the hon． Minister was pleased to state that if there was any vacancy，they would be absorbed．But uptil now，no steps have been taken．I again request him through you to look into the matter and give them work．

Mr．Chairman：The hon．Member has taken more than ten minutes．

Shri M．B．Thakore：I did not speak in 1960．So kindly give me some more time．

Mr．Chairman：I am not responsi－ ble for that

Shri S．V．Ramaswamy：It is time－ barred！

Shri M．B．Thakore：Regarding my cut motion No． 378 about the need to shift the headquarters of the Western Railway from Bombay to Ahmedabad， I do not understand why after the separation of Gujarat and Maharash－ tra，still the headquarters of the Wes－ tern Railway has not been shifted．

Shri Shahnawaz Khan：The railway headquarters has nothing to do with the State headquarters．

Shr M．B．Thakore：That is true but the majority of the lines and the trains are passing through Ahmedabad－ up and down．I think it will be most advisable for the Railway Administra－ tion to shift the headquarters of the Western Railway to Ahmedabad．I think Shri Ram Krishan Gupta also suggested that the headquarters of the Western Railway may be shifted from Bombay to Ahmedabad or Ajmer．

Shri T．B．Vittal Ras（Khammam）： That is what the Estimates Committee also recommended．

Stri Shahatwas Thas：What is his proposal－Ahmedabad or Ajmer？
Ent M．B．Ttriere：．Ahtedabed． There they will get buildinge and get land on which they can construct quarters．

Then I would talk about reducing overcrowding on the branch line fram Mehsana and Ahmedabad．I have written so many times to the Deputy Ministers and the Minister．I have seen the General Manager also．But they have not taken any action on all my suggestions．I say that there should be a double line from Ahmeda－ bad to Abu Road and Marwar，that is， Ahmedabad to Marwar．Then I sug－ gested doubling the line from Kandla to Palanpur．Then I recommended the introduction of some more trains from Mehsana to Abu Road and from Ahmedabad to Mehsana．Also on all branch lines they should at least attach two or three bogies more in the summer season．

Mr．Chalrman：Shri B．D．Mishra．
धी भ० ती० मिब्र（केसरगंज）： मभार्पनि जी，रेन्ववे मंश्राय ने मर्वतोमुली उम्रति की है इममें कोर्ट मन्देह कर्ने की बात नहीं है । लेकिन उसकें माथ ही माथ हिमाे मानेनीय मदस्य ंें प्राकंड़ों के बतानें के बाद यद्न निडिचन है कि कमंचान्यो की मंब्या में जिस कदन वृद्यि की गयी है उननी ही द्रेश्वमेग्व में कमी हो गंयी है ।

जश्रां नक द्वेग्वरेख्व की बात है，मं ममभ ता द⿳亠口冖又丶 कि पषिक：मे भष्षिक कमं बानियां के होने हुए भी मकाई में भी उनरी ही कमी नफ़ पाती है जिननी कि．कमी इनने कमंशन्यिों के ह़ोने हैए नहीं होनी चालिए।

घी शू० बं० घंक（कंषण）ह刀 मएक्यमे में मरी लीर बालिए।

बो म० ती० सिख्वानमहुकमें मे परी घोर बाहिए，यह मानर्भाप मदटन का सुलाब है मे तों केवल इलना ही कह． $\boldsymbol{\pi}$ fि पर्याष्ठ नोग मीज़य है，मावश्यकला fिकी तेतरेज की बोण व्याम 就 की है।


थी म० मी० मिस: जहां मेने इस किजाटेमेंट की मवतोन्मूली उस्रति की बात कही वहां मुफे एक संस्टृत की कहाबत याद भ्ञाती है जो कि इस प्रकार है :

गजन् कृक पारगाभ: त्वर्वय मंत्वं वषंनि भ्रभाग्य क्षत्र संघ्रे मयि नायान्ति विन्दव :।।

प्रप्षात, प्रापकी मब नरह उदार दृवि होने हए भी जोर मब तरफ सोने की वर्षा होते हए मी मेरे ऊपर कनक की एक दूध तक नहीं प्रायी। यह कहावत मुफे आंच नाइनों के सम्बन्ष में कहनी पड़ी है।

रेलबेज का मेन लाइंम की तक्फ ध्यान गया है। लेकिन जहां नक ांच लाइस का सम्ब्बम्ष है, बी० एन० उन्नू० रेलवे जब चल गही थी, जब कम्पनी की यह रेलवे थो, वह भाज तक उसी भ्रपनी पु गनी श्रवस्था में पड़ी हुई है । एक, एक स्टे गन पेंये बने हुए है जहां सम्भवत: स्टेगन मास्टर के वर्े होकग टिकट बांटने के प्रलावा भोर कोई जगह ही नहीं है। मंने पिछ्घले मान भी प्रापका ध्यान दिलाया था कि. वूर्वोतर रेलवे मे बहराइच जिने में नानपाग से बतर्गनया घाट जो लाइन जाती है
 कि. विसी भी ममय जाड़े में, गर्मी में प्रथता बरसात में $? 0$ प्रादमी भी इकट्ठे बड़े हो सकें। पिष्बनें माल मीहपुर्वा म्टेशन पर एक क्र बहुत घ्बोंटा मा घोष्ठ बनागा गता है जहां $f$ क में ममक्षना हू कि $x_{0}$ मादमी बड़ी मुधिकल से बंठ मकेंगे, नेकिन बहां मलादा उस घोटे से पोर बनाने के पोर किसी किस्म का मुषार नही किया गया है। वहां पर कोई भी किसी प्रकार का पानी का प्रबन्व या वर्षा भयवा यीष्म कतु के कोप से बबने का प्रत्ष भैना स्थान नही है।

इसके पलावा पाप वेलें कि बहा पर गार्पाया की क्या स्थिति है। में जानता हृं कि कभी-कभी हमारे जनरस मं तेषर जो कि उष रेलबेज के हैं वे क्ता पर धपनी हुषणित्व

गाडियों के भ्रन्दर जाते हैं लेकिन वह गाईियां जिनमें कि जनता चलती है उनकी क्या प्रवस्पा है । श्रगर में श्रधिक न कहूं तो यह कह मकता हूं कि मम्भवत: इन पांच, दस वर्षों में उनकी कोई मग्म्मत नहीं हुई है मोर वह उमी श्रपनी पुगनी हालत में चल रही हैं।

तृतीय श्रेणी की गाड़ियों के मम्बन्ष में तो मम्भवतः गेलवे प्रशामन का घ्यान ही कंम जाता है । में देबता हूं कि फस्ट घोर मेकेंड बलाम की गाड़ियों की भी कमोवेश वही भ्रवस्था है। लवनऊ मे नेंगालगंज रोड तक जो एक. डिब्बा नगना है उस डिब्बे को यदि भ्राप देवने की केष्टा करें तो श्राप पायेंगे कि उसमें भीज़ घ्रत्यधिक. होने के कागण जगह बहुन क:म रहती है। गांडे में एक बजे या दो बजे बह गाड़ी पहुंचती है इसनिए हर श्रादमी चाहना है कि वह उममें बंठ कर नंगालगंज नक. पूरो गन का मफर कर मके। मेग मुकाव है कि इसके लिए एक दूरी बोंगी प्रलग मे उममें नगनी वानिए । घ्रत हानत यह है कि यडं कल। में रो किमी नरीकें में जगह नहीं fमलर्ता। फम्डं क्नाय श्रोग चेक्रंड क्रास में भी करीब-रोत्ब गही ह़ानत है। बांगीज की मम्भवन: दार-नीन वंयं मे मफाई नहीं हुई माल्य म हृंती है। कांनेज की भो तुरी हालत है। मेग कहना है कि तांच नादंत की तरफ भापका विशोष ध्यान जाना चाहिए भोर उनके स्टेशानों मोग गाड़ियों के सुषार की तरफ विरोष क्प से ध्यान दिया जाना बाहिए।

मैं तो भपने तईं रसको एक बहता बत़ी सुविषा समकता हां कि स्ट्यानों पर साक मिह्टी रजने की म्पषस्षा की गई है। उससे मी कुष्ष काम चलता है क्योंकि यानी लोग थोषादि जाने के बाब हाब जोने के लिख उतरवे हैं पीर उन्टं मिह्टी की जहरत पड़़ी हैं मेंकिन धापने मी देषा छोगा फोर मेरा भनुमव ही मीर इसके fिए कंने समय-समय पर स्टेघन मास्टर से कहा है कि क्यों साइष यह् बहां पर मिद्दी

रसने की जगह तो भ्रापने बना दी है लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि वहां पर मिट्टी बरी भी है कि नहीं घ्रोर 5 , 5 रोज तक मिट्टी नईी रक्खी जाती है । भ्रापको इसकी बेसरेख रसनी चाहिए कि यह ओ मिट्टी की सुविषा प्रदान की गई है वह वास्तव में घ्रपनी जगह् पर मौजूद भी है कि नहीं। भगर रेलवे प्रशासन, जां मुविषएां उसने जनता को दी है, उनके बारे में देखेरेख बनाये गक्खे तो जनता को प्रधिक मे प्रधिक लाभ हो सकता है लेकिन उनकी देखरेख्व की कमी है । में श्रापका छयान मभापनि महोदय के जग्एिए दिलाना चाहना हूं कि श्राप काफी रुपया खचं कर रहे हैं, घ्रापने सुविधाएं दी हैं, श्रापने किराये भी काफी बढ़ा दिये हैं भोर इममें भी कोई मन्देह नहीं कि किगया प्रापको जेब में जाता है लेकिन जितनी मुविषाएं जनता को मिल ? चाहिएं उननी उसको नहीं मिन्नती हैं। इसके लिए में भ्रापका ध्यान श्रार्वाषत कर्ना चाहता हूं।

प्रथम श्रेणी पौर दितीय श्रेणी के लिए कंडकरस्स मुकरंर हो गये हैं लेकिन तृतीय श्रेणी में ऐमी कोई क्यवस्थi विध्यमान नहीं है। तीसरे दर्जें में बड़ी रेलपेल रहती हों पौर हम देबते हैं कि ब़़े प्रोर एक बुठिया दोड़ते हैं लेकिन गाड़ी नहीं पाने हैं मोर गाड़ी धूट जाती है। इसलिए जहरत इस बात की है कि तुतीय श्रेणी के लिए मी कंडक्टर या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जो कि उनको गाड़ी में बिणा सके। इसलिए में समझता हूं कि तृतीय श्रेणी में हुविषापों के विये जाने की पोर भ्रापका पषिक मे पषिक घ्यान जाने की पाबर्यकता है ।

इसके पलाबा मैने बो सुकाब आापके सामने पौर रक्से चे । जिस समय मानतीय जी लाल बहादुर थाए़ी रेसबे मंत्रालय में काम कर रदे वे मेंने वहु सुसाब पेश किखा था कि जरनस तोट मे बहराइप किनग होते है सोहेमषा अंगम तक एक माइन निकाली आये। इस लाइन के निकालने की खर्षा मी चनी बी

मोर सम्भबतः उसका सरें भी हो चुका था । मुमे विक्षले साल भी यह कहा गया था कि तृतीय पंबवर्षीय योजना के दोरान सम्भपत इस पर बिषार होगा लेकिन मुभे बेद हैं कि इस साल में भी मैंने उसे नहीं देसा है। में इस भबसर पर उसकी पोर पुनः मंत्री महोदय का घ्यान भार्काषत करना चाहृता हू होर उसके बनने से जनता को काफी सुविषा होगी, कन्चे माल के लाने की सुविषाएं भी बहुत बक़ जायेंगी प्रौर उसी के साथ-साय रेलवे विभाग को मी प्रषिक से पषषिक लाभ होगा ।

कतरनियाषाट जो कि बहगइष जिले में है वहां से कोड़ियालाषाट तक $\varepsilon$ मील का फासला हैं जिसके कि बीच में गेलक्षा नदी पड़ती है तो मेरा मुमाब है कि इस नदी के ऊपर बीच में एक क्रिज बना कर गेलेखे लाइन निकाल दी जये तो उससे बड़ी सुविषा हो सकती हैं। परिषमी जिलों अंमे निनीताल पोर महाग्नपुर से बहां तक जाने की बहुत सुकिषा हो सकती है जब कि इषर गोंडा, लबनऊ घुम कर बराबर जाते हैं। जहां पोड़े मे बर्बं मे प्रधिक सुखिषापों प्रोर पषिक लाभ होने की सम्भाबना है तो उस बर्वं की तरफ घ्यान देना बाहिए। इसिए यह कोड़ियालाषाट का तो तिज बनाने की घात हैं पीर उस Tर से होफर रेलवे लाइन निकालने का मुभाब में प्रापके सामने पहले मी चे चुकां हूं मीर प्षाज किर उसको दुराते हे भाषा करता हें कि प्राप उस नरफ प्रषिक ध्यान देने की कोशिए कमेंगे ।

इसके परितिक्त हमारे कर भाइयों ने किपाटेमेंटल क्नित्टीन के बारे में भिम्र-भिज किजार प्रकट किसे है। । कुष्ष वोग काते है कि पहूले रेलके में गो ठेकेदारी fिस्टम बलता था
 को इस घात की किन्ता रहती की कि कहीं जाहक पर्षात् याती लोग किसी तरह मे भोबन से घसन्तुष्ट पह हो आयें मीर बह सोषता बा
 से किलेगीं दीर कम बाम में किलेंी तो भूमाकिए तोग पषिक्ष को की केष्टा करें कीर

## [श्री म० दी० मिश्र ]

ठेकेदार को घ्रधिक लाभ मिलेगा । लेकिन जब से कैटरिरग का रेलवे की तरफ से खुद इंतजाम ठुप्रा है श्रोर जमा कि घ्रधिकतर लोगों का स्याल है जिनके जिम्में यह काम है वह लापरवाही घ्रोर कुद्र उपेक्षा का भाव रखते हैं क्योंकि वह् पेड सवेंटस होते हैं, रेलवे से माहवारी तनरुवाह मिलती है श्रोर इमलिए वहु उतनी मुस्नेदी श्रोर इंटरिम्ट मे काम नहीं फरते। में चाहता हं कि रेलवे प्रशायन को इम कैटर्टरंग के काम के ऊार स्रधिक देख्वग्ग्र कर्नी चाहिए।

एक माननीय गदम्य ने जो रोटी का स्टंन्डंड ग्रने का मुआव दिया था वद्ध उचित ही था क्योंवि उसके ग्रभाव में शोड़े मे श्राटे के चार फुनके हनके-हलके बना कर गम्ब दिये जाते हैं ग्रोर जो नोग कि दो, दो श्रोर चार, घार मर्तंत्रा नाइता नहीं कर्ने उनके लिए वह् नाकाफी होना है । फुलके जो दिये जायें वे इतनी लोई के तो हों कि जनसाधारण के लित् पर्यव्त हों। इयेलिए मेरा निवेदन है कि गेलवे प्रशासन को भ्रपने इम डिपांमेंटल कैटर्रिग के बारे में जरा ज्यादा ध्यान देना बाहिए प्रौर यहु देखना चाहिए कि जनता को उधित मुनामिब दाम पर वर्याप्त भाँजन प्राप्त हो ।

इसके प्रतिरिक्त एक बात मुझे श्रौर कह्नी है । रेलवेज के बारे में जनभुति यह् हैं कि यहा पर नियुक्ति के लिए भ्षष्टाषार का सहारा लिये बिना किसी प्रकार भी सफलता नही मिल सकती है । पब हमारे देका में हर जगह् प्रष्टाषार है, हर विभाग में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भष्टाषार है ऐेसी बनभुति है लेकिन पह्ह जनभुति रेलवे के बारे में मपेकाकृत कहीं मषिक है मोर मुक्षे रेलवेज के जिम्मेबार भार्दमियों के बारा मालूम हुमा है कि साइए इस विभाग में प्रवेशा पाने के लिए शष्टाबार की पाषष्यकता क्ड़ती है। मे घयने रेलबे मंनी मद्रोष्य का ज्यान हस धोर

विशोष रूप से ग्रार्करित करना धाहता हूं । जब श्रापके यहां इतनी जगहें होती हैं घौर इस कदर पिछले दो, तीन वर्षों में नियुक्तियां हुई हैं तो इम बात की बहुत जरूरत है कि इस घोर ध्यान दिया जाये कि वास्तव मे वे ही लोग नियुक्त हों जो कि उसके लिए योग्य हों । उपयुक्त नियुक्तियां न होने का ही परिणाम हम देखते हैं कि एक गाड़ी लाइन पर खड़ी होनी है मालगाड़ो उषर खड़ी होनी चाहिए लेकिन ठीक पर्टरियंं की बदर्ली न होने के कारण ग्रोर मम्त्रन्धित कमंचारियों की लापर्वाही के कागण गार्ड़यां ग्रापम में टकरा जार्ता है ग्रोर जान-माल का बहुत नुक्सान हो जांता है । मंग तो ग्राना नग है हि: श्रशंन नियुक्तिया कंग्ने समय माववानं बर्तो गई होनों ग्रौर उपयुना पाश्रों को हीं नियुक्त किया जाना तो ரेमी गर्ननियां नह़ी हो गकती थीं। इसलिए, में श्रापका इस म्रोर :यान ग्राक.षित करता चाहत्ता हूं कि नियुक्तियों के मम्बन्ध में जों यह् श्रपवाद या जो जनश्रुति चल रही है उसको दूर करने की पूरी चैप्टा की जाये । इन गब्दों के साथ में क्रपनी चर्चा समाप्त करना हैं ।

Shri Harish Chandra Mathur (Pali): Mr. Chairman, Sir, I will not add to the long list of railway lines demanded for new construction. Not that Rajasihan has not got such a demand. I also appreciate this demand coming from the various quarters in an underdeveloped country. I will confin ${ }_{e} \mathrm{my}$ observations to the working of the Railway Board, and to certain important matters of policy pursued by the Railway Board.

I have no hesitation in conceding that since 1945, when the railways were in a completely ramshackle condition, they have made vast improvementa, and they have gained in strength from year to year. The progreas has been a really very strike in cortain directiong, particulariy the production side, where we almost
expect to gain self-sufficiency, and where our demands for foreign exchange have been very considerably reduced. This all goes to the credit of the railways, and the authorities from the International Bank and others who have come here have also paid handsome tribute to the railways.

I fully concede that we have got to pin-point our attention to certain very important measures. You will remember that on the floor the House, more than a year back, in answer to more than one question, the hon. Minister of Railways said that we were selfsufficient in wagons, that we were in a happy position to export wagons. It is just the same as at the end of the First Five Year Plan we were saying that we were self-sufficient in food and that there was no danger. We are planning in a haphazard manner. Now, you find how we are bottle-necked in everything. We find ourselves handicapped at all steps, whether it is the movement of steel, or the movement of coal or of other things.

I was very much surprised when I was told today that the same unfortunate condition obtains in the matter of food also. As a matter of fact I had asked the question only from that point of view. Why don't you stagger the movement of your food when you are self-sufficient in food, when you have got food all over? The hon. Minister Shri Patil is giving us the impression that we are surplus in food at every place. So, I thought we might stagger the movement of food so that certain wagons could be released to facilitate the movement of other items.

We have had explanations on this matter from the hon. Minister of Railways as also from the han. Minister of Steel, and Mines. But I have no hesitation in saying that nobody in this House feels at all satisfled Nobody seems to be at fault. The Railways say that they have done their best, that they have fulalled their targets. The hom. Minister of Steel, Mines and Tuel sayn that everything is eotng according to plan, that we are in the best
of co-ordination. If both of them have been proceeding according to plan and if everything is going on in full coordination, what is all this trouble about? We find 13 million tons of coal lying at the pit-heads.

When I went down to the south, in Bangalore and other places, to my very great surprise, I was told that the small-scale industries were completely starved. They could not get their demand of mere 300 tons for the last 6 months.

We are now so keen on our production and the entire future of our country. The entire economy of the country depends upon increased production. If such bottlenecks are created because of the most inefficient planning of the public sector-either it is in the Railways or it is in the Ministry of Mines and Stecl-then, it gives a very grea! set-back. I do not know how the Railway Minister says that within the next 6 months the situation will ease. Wha: will happen in 6 months' time? Could not that happen earlier? If the situation would be eased within the next 6 months why was not something done earlier? We have been bringing this matter all the time to the notice of the hon. Minister, that there is a bottle-neck, that the smallscale industry is suffering, that the large-scale industry is suffering. That is the most important matter. When that is so, we find them speaking, either from Jullundur or from Calcutta as if everything is all right. I could understand departmental heads speaking in that manner. But when hon. Ministers speak, we expect them to speak not for the Railways, not for the Mines or Coal but for the Government. When they speak for Government, I fail to underatand how such dislocation has happened. The House must be taken into confidence and we must know why there was this dislocation and where there was no coordination.

We have just heard that a committee is going to be appointed under the chairmanshitp of the Finance Minister
[Shri Harish Chandra Mathur]
to devise ways and means to get over this bottleneck. It is all right. We very much welcome the appointment of that committee. But, I would strongly suggest that there should be a Standing Committee which should meet every month. This Standing Committee must represent at the highest level the Ministry of Commerce and Industry, the Ministry of Food, the Ministry of Steel, Mines and Fuel and also the Ministry of Railways; maybe under the chairmanship of the Minister of Railways. They must meet every month; they must take complete stock of the whole situation and we should know the co-ordinated position. We do not want the Chairman of the Railway Board issuing statements that the Railways have fulfilled their targets and the Controller saying something. l sent a certain letter and that letter has been forwarded to the Controller of Coal Movements. This is the state of affairs. The country will not be satisfled though the departmental heads may derive the satisfaction that they have fulfilled their targets. I therefore dmand that this Standing Committee should be appointed.

Another matter to which I would Iike to refer is the question of dieselisation. The hon. Minister of Finance has been telling us all the time that he wants a shift from diesel to petrol and that his taxation measures are devised with a view to that end, so far as road transport is concerned. I asked a question whether as a result of his taxation measures there has been any shift. He said that they were not at present in a poation to give a really sound picture but they have every reason to believe that there has been a shift. The other day the Minister of Transport told us that the shift has been completely on the other side, that there has been a shift from pertrol to diesel, can absorb more tax please tax it; but do not let the country get wrong impression that we are switching on to a more inefficient type of fuel. If we are short of diesel is there
any justification for the Railways now to shift or to switch on to diesel?

The other day the Railway Minister said that we will have to lay 3 or 4 tracts. Have we examined the economy? I do not want vague general statements. We want to know definitely what is the examination which they have made of this important matter. When they are getting a diesel track of 3800 miles what is the economy of that? How is the entire future economy of the country going to be affected by this? What is our diesel requirement and what is the total foreign exchange we are going to spend on it? Has the Cabinet examined it. It is not enough that the Railway Board has examined it. Has the Cabinet come to conclusions? What would be the development so far as the entire economy is concerned?

There are two other matters to which I would like to refer about the working of the Railway Board. Certain hon. Members from the other side said that there has been a cut in the number of Class III and Class IV servants and asked why it should be so and why should there not be a cut in the number of officers. I think the criticism was not very sound. This cut in the number of Class III and Class IV servants in the Railway Board is very much welcome because the Railway Board is not functioning in the field. They are doing planning. When they are doing planning you do not need so many class IV servants, so many chaprasis to be appointed. This is very much welcome. But the Railway Minister also told us that he was going to effect a certain economy in the rest. He made mention of it last time. $\mathrm{H}_{\mathrm{e}}$ said one of the Deputy Directors was being retrenched and further economies are being examined. I do not know whether they have examined the further economies and what those economies are.

I would submit that the Railways will not be able to do really much steamlining of their administration
unless and until they examine the entire structure of working. It is a strong feeling with me that there is unnecessary concentration of work in the Railway Board. It is true that there has been considerable delegation of power, from the General Managers downwards. There has been delegation of power for the efficient working of the Railways but there has been very little release of work. It is a general tendency; I do not blame anybody. The Members of the Railway Board may be very efficient but still ther is an unhappy tendency for the concentration of work and power.

If you refer to the Draft Outline of the Third Five Year Plan you will find that a very pointed reference has been made there that unhealthy tendency in the Secretariat is all over In every Ministry.

The Railways are, fortunately or unfortunately, no exception to that unhealthy tendency of concentrating power. I wish that there is a little relief of work and they concentrate themselves only on important work.

Mr. Chairman: Is he likely to take more time?

Shri Harish Chandra Mathur: Yes, Sir.

Mr. Chairman: He may continue next time.

## $15 \cdot 30 \mathrm{hrs}$.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

## Seventy-Etgeti Report

Shri Jhulan Sinha (Siwan): I beg to move:
> "That this House agrees with the Seventy-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th March, 1961."

Mr. Chairman: The question is:
"That this House agrees with the Seventy-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th March, F961."

The motion was adopted.
15.301 hrs.

ESSENTIAL COMMODITIES (FIXATION, REGULATION AND CONTROL OF PRICES) BILL* by Shri Narayanankutty Menon.
Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for flxation, regulation and control of the prices of commodities which are essential for the life of the community.

Mr. Chalrman: The question is:
"That leave be granted to introduce a Bill to provide for fixation, regulation and control of the prices of commodities which are essential for the life of the community."

The motion was adopted.
Shri Narayanankutty Menon: Sir, I introduce the Bill.

### 15.36 hrs.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL*
(Amendment by section 4) by Shri Keshava.

Shri Kechava (Bangalore City): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894.

Mr. Chairman: The queation is:
"That leave be granted to intro-
duce a Bill further to amend the
Land Acquisition Act, 1894".
The motion was adopted.
Sher Eeahava: Sir, I introduce the Bill.

[^1]Extraordinary Part IL-Section 2,


[^0]:    "That the Bill be pessed."
    Mr. 8peaker: The question is:
    (Interruption). An hon. Member does not know when I am goting to

[^1]:    ${ }^{\bullet}$ Published in the Gazette of India dated 10-8-61.

